WWW.Kanchanujala.in

हिन्दी दैनिक

kanchanujala14@gmail.com

कंचन उजाला

लखनऊ से प्रकाशित

सच्चाई के साथ

वर्षः 01 अंक : 277 | लखनऊ, शनिवार, 25 सितम्बर, 2020 | पृष्ठ- 6 | मूल्य - 1 रुपये

एक्ट्रेस टिया बाजपेयी ने करवाया अपना ड्रग टेस्ट

तीन राज्यों में किसान आंदोलन

पंजाब में दिनभर बाजार बंद रहे, दिल्ली बॉर्डर पर जल्दी ही वापस लौट गए प्रदर्शनकारी

नयी दिल्ली, एजेंसी। हाल ही में सदन से पास हुए किसान बिल को लेकर देशभर में शुक्रवार को किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब और हरियाणा में बंद का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। किसान सुबह ही सड़क और रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, जगह-जगह चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन किया। यहां पूरे दिन बाजार बंद रहा। दिल्ली बॉर्डर और पश्चिमी यूपी में किसान प्रदर्शन के लिए सड़कों पर तो निकले लेकिन बंद का मिला जुला ही असर रहा। वे दोपहर बाद घर लौट गए। भास्कर की टीम किसान आंदोलन को कवर करने के लिए पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड पर मौजूद रही। पंजाब के मानसा शहर में भारत बंद का असर साफ नजर आ रहा है। सिर्फ सड़कें ही नहीं रेल की पटरियां तक किसानों के आक्रोश की गवाही दे रही हैं। पंजाब के अलग-अलग 31 किसान संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया है। इसमें सबसे प्रमुख भारतीय किसान यूनियन (उग्राहां) जो इस आंदोलन का यहां नेतृत्व कर रही है।

पंजाब के कई लोक कलाकारों ने भी किसानों का समर्थन किया है। जहां दलजीत दोसांज जैसे बड़े गायकों ने किसानों के समर्थन में सोशल मीडिया पर आवाज उठाई है

वहीं, सिद्धू मूसेवाला जैसे गायक किसानों के समर्थन में सड़क तक उतर आए हैं। किसानों को सिर्फ लेफ्ट पार्टियों का ही नहीं बल्कि अकाली दल जैसी राइट विंग पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। पंजाब में भाजपा के अलावा अन्य सभी पार्टियों ने किसानों की मांगों का समर्थन किया है। पंजाब बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी किसानों के समर्थन में आंदोलन में शामिल हुए हैं। पंजाब-सिरसा हाईवे पूरी तरह से जाम है। हजारों की संख्या में किसान यहां इक्ट्ठा हुए हैं। इन किसानों को पंजाबी लोक कलाकारों का भी समर्थन मिल रहा है। अभी-अभी पंजाबी कलाकार सिद्धू मूसेवाला यहां किसानों के समर्थन के लिए आए हुए हैं। वे किसानों को संबोधित कर रहे हैं। मानसा जिले के कैंचियां इलाके में अकाली दल ने ही रोड ब्लॉक की है। अकाली दल के झंडे तले कम ही किसान नजर आ रहे हैं। किसानों की सबसे ज्यादा संख्या भारतीय किसान यूनियन (उग्राहां) के जत्थों में ही दिखाई दे रही है। ज्यादातर किसान राजनीतिक दलों को अपने प्रदर्शनों से दूर रखते हुए सिर्फ किसान यूनियनों के झंडों के साथ ही सड़कों पर हैं। शाम पांच बजे के बाद प्रदर्शनकारी अपने घर के लिए निकल गए। कुछ दुकानें अब खुलने लगी हैं लेकिन अधिकांश बाजार अब तक बंद है। किसान यूनियन के प्रतिनिधियों का कहना है कि बंद का उनका आह्वान पूरी तरह सफल रहा और सिर्फ किसानों का ही नहीं बल्कि हर वर्ग का समर्थन उन्हें इस बंद के दौरान मिला।

आजादी के बाद किसानों और मजदूरों के उत्थान के नाम पर खोखले नारे दिये गयेः मोदी

नयी दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आजादी के बाद दशकों तक किसान और श्रमिकों के उत्थान के नाम पर देश और राज्यों में अनेक सरकारें बनीं लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। श्री मोदी ने जनसंघ के स्थापकों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसानों, मजदूरों और महिलाओं के उत्थान के नाम पर खोखले नारे दिये गये।उन्हें सिर्फ वादों और कानूनों में उलझा कर रखा गया। एक ऐसा जाल जिसको न तो किसान समझ पाता था और न ही

श्रमिक। उन्होंने कहा कि आजादी के कई दशकों तक किसान और श्रमिक के नाम पर खूब नारे लगे, बड़े-बड़े घोषणापत्र लिखे गए लेकिन समय की कसौटी ने सिद्ध कर दिया कि ये सारी बातें कितनी खोखली थीं। देश इन बातों को भली-भांति जानता है।

छह दिन तक कम रहने के बाद फिर बढ़े कोरोना के सक्रिय मामले

नयी दिल्ली, एजेंसी। देश में लगातार छह दिन तक कोरोना महामारी को मात देने वालों की संख्या संक्रमण के नये मामलों से अधिक रहने के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान इनमें कमी दर्ज की गयी और इस दौरान जहां 81,177 लोग कोरोनामुक्त हुए, वहीं संक्रमण के उससे करीब पांच हजार अधिक 86,052 मामले सामने आये, जिससे सक्रिय मामलों में 3,734 की वृद्धि हुई। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 86,052 नये मामले सामने आये हैं, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 58,18,571 पर पहुंच गयी है। इसी अवधि में 81,177 मरीज स्वस्थ हुए हैं जिससे कोरोनामुक्त होने वालों की संख्या अब 47,56,165 हो गयी है। संक्रमण के नये मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या कम होने से पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों की संख्या 3,734 बढ़कर 9,70,116 हो गयी। इससे पहले छह दिन तक लगातार स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रहने से सक्रिय मामलों में कमी आयी थी। सक्रिय मामले शनिवार को 3790, रविवार को 3140, सोमवार को 7525, मंगलवार को 27,438, बुधवार को 7,484 और गुरुवार को 1,995 कम हुए थे। इसी अवधि में 1,141 मरीजों की मौत हुयी, जिससे संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 92,290 पर पहंच गयी है। देश में सक्रिय मामले 16.67 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.59 फीसदी रह गये हैं जबकि, रोगमुक्त होने वालों की दर 81.74 प्रतिशत हो गयी है। कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामले 1,521 बढ़कर 2,75,404 हो गये हैं जबकि 459 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 34,345 हो गयी है।

प्रख्यात गायक एस पी बालासुब्रमण्यम नहीं रहे

चेन्नई, एजेंसी। खनकती एवं सुरीली आवाज से गायकी की दुनिया में अलग पहचान बनाने वाले लोकप्रिय पार्श्वगायक एस पी बालासुब्रमण्यम का शुक्रवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद श्री बालासुब्रमण्यम को पांच अगस्त को यहां के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गाया था। अस्पताल ने आज अपराह्न मीडिया को बताया कि श्री बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया। अस्पताल प्रशासन ने कल शाम स्वास्थ्य बुलेटिन जारी करके प्रख्यात गायक की स्थिति अत्यंत खराब होने की सूचना दी थी। श्री बालासुब्रमण्यम के पुत्र एसपीबी चरण ने पिता के निधन की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अपराह्न एक बजकर चार मिनट पर अंतिम सांस ली। संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह के निधन की खबर से प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है। श्री बालासुब्रमण्यम की लाजवाब एवं सुरीली आवाज ने विश्वभर के संगीत प्रेमियों को उनका दीवाना बना दिया था। पांच दशक तक उन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने श्री बालासुब्रमण्यम के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री राव ने अपने शोक संदेश में कहा कि हजारों गीतों को सुरीली आवाज देने वाले और प्रशंसकों द्वारा बालू के नाम से पुकारे जाने वाले श्री बालासुब्रमण्यम ने विश्वभर में अपने प्रशंसक बनाये। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि चिकित्सकों और अन्य मेडिकल स्टाफ की हर संभव कोशिश के वाबजूद श्री बालासुब्रमण्यम को बचाया नहीं जा सका। उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने शोकसंतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

बिहार विस के लिए 28 अक्टूबर से तीन चरणों में मतदान

मतगणना 10 नवम्बर को

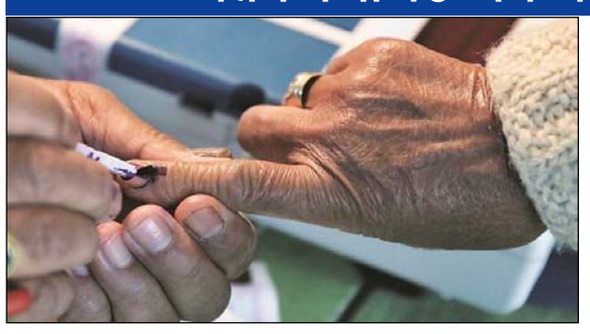

नयी दिल्ली, एजेंसी। कोरोना महामारी के साये में बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के लिए चुनाव तीन चरणों में 28 अक्टूबर, तीन नवम्बर और और सात नवम्बर को होंगे, जबकि मतगणना 10 नवम्बर को की जायेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बहुप्रतीक्षित बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि चुनाव तीन चरणों में 28 अक्टूबर, तीन नवम्बर और सात नवम्बर को होंगे। तीनों चरणों की मतगणना एक ही दिन 10 नवम्बर को होगी। पहले चरण में भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले में मतदान होंगे। दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले में मतदान कराये जाएंगे। तीसरे चरण में पटना, बक्सर, सारण, भोजपुर, नालंदा, गोपालगंज, सीवान, बोधगया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले में मतदान होगा। उन्होंने बताया कोरोना संक्रमण के कारण क्वारंटीन में रहने वाले मतदाता या तो पोस्टल बैलट से मतदान कर सकते हैं या फिर वे अंतिम चरण के चुनाव के दिन अपने-अपने मतदान केन्द्रों में स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में मतदान करेंगे।

सुशांत के पिता के वकील बोले, केस की जांच भटक कर ड्रग्स की ओर चली गई

नई दिल्ली, एजेंसी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत अभी भी लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। इस केस की जांच तीन-तीन एजेंसियां कर रही हैं लेकिन इस केस में कितनी सफलता अब तक मिल पाई इस को लेकर सुशांत के परिवार वाले चिंतित हैं। सुशांत सिंह केस की जांच अब बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की ओर जाने के बाद सुशांत सिंह के परिवार के वकील विकास सिंह ने चिंता जाहिर की है। विकास सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ÷सुशांत का परिवार ऐसा महसूस कर रहा है कि जांच अलग दिशा में जा रही है। सभी ध्यान अब ड्रग्स केस की तरफ मोड़ दिया गया है। एम्स के डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि सुशांत की मौत गला घोंटने से हुई है। सुशांत के पिता के वकील ने आगे कहा, आज हम असहाय हैं क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि केस किस दिशा में जा रहा है। आज की तारीख तक, सीबीआई ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है जिससे पता लग सके कि उन्हें क्या मिला है। जिस गति से जांच हो रही है उससे मैं खुश नहीं हूं। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब जांच की तो बॉलीवुड से ड्रग्स कनेक्शन के तार जुड़ते चले जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में बॉलीवुड की बड़ी ड्रग्स मंडली एनसीबी की रडार पर है। ड्रग्स केस में बॉलीवुड की कई बड़ी एक्ट्रेसेज के नाम सामने आए हैं। शुक्रवार को रकुलप्रीत सिंह से एनसीबी ने पूछताछ की। अब खबर आ रही है कि रकुल ने इस बात को कबूला है कि उन्होंने रिया से ड्रग्स को लेकर बात की थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, रकुल प्रीत सिंह ने ये माना है कि साल 2018 में उन्होंने रिया से ड्रग्स को लेकर चैट की थी।

हमारा किसान प्रगतिशील किसान है, वह नया अनुसंधान चाहता हैः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कृषि विज्ञान केन्द्र, हापुड़, बुलन्दशहर तथा मुरादाबाद के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर वर्चुअल माध्यम से कृषि विज्ञान केन्द्र, हापुड़ के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण एवं कृषि विज्ञान केन्द्र सम्भल, कृषि विज्ञान केन्द्र बुलन्दशहर तथा कृषि विज्ञान केन्द्र मुरादाबाद (द्वितीय) के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा किसान प्रगतिशील किसान है, वह नया अनुसंधान चाहता है। नये तौर-तरीके के साथ अपनी खेती को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे नये तौर-तरीके कौन बताएगा। यह उसके सामने एक प्रश्न रहता था। विगत 03 वर्षों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की नई श्रृंखला ने किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ उन्हें उन्नत किस्म के

बीज उपलब्ध कराने में मदद की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक किसान को उसकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके, इस पर जोर दिया गया। 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना', 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रत्येक किसान को 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के साथ जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, जिनके प्रयासों से कृषि क्षेत्र में नई प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हुई है, जो किसानों के व्यापक हित में है। अब किसान 'वन नेशन, वन मार्केट' के नये युग की ओर जा रहा है, जहां वह अपनी उपज की देश के अन्दर कहीं भी बिक्री करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इसके साथ ही, शासन उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारण्टी भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ना ही होगा। अगर किसानों की आमदनी बढ़ानी है, तो कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलाव को हमें खुले दिमाग से स्वीकार करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहें, इसके लिए राज्य के सभी कृषि विश्वविद्यालय व सभी कृषि विज्ञान केन्द्र इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

राहुल ने किसानों से किया डिजिटल संवाद बोले,मोदी सरकार पर रत्ती भर भरोसा नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों किए गए भारत बंद का समर्थन करते हुए शुक्रवार को विभिन्न रायों के कई किसानों के साथ डिजिटल संवाद किया। उन्होंने इस दौरान दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कृषकों को रत्ती भर भरोसा नहीं है।उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि संसद से पारित कृषि संबंधी विधेयक देश के किसानों को गुलाम बना देंगे। किसानों से बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसानों से बातचीत करके एक बात साफ़ हो गई कि उन्हें मोदी सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। किसान भाइयों की बुलंद आवाज़ के साथ हम सब की आवाज़ भी जुड़ी है और आज पूरा देश मिलकर इन कृषि क़ानूनों का विरोध करता है। कांग्रेस नेता के साथ डिजिटल संवाद में महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा और कुछ अन्य रायों के किसान शामिल हुए। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक अन्य ट्वीट में दावा किया, एक त्रुटिपूर्ण जीएसटी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बर्बाद कर दिया। नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बना देंगे। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने भी किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया और आरोप लगाया कि ये कृषि विधेयक ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाते हैं। प्रियंका ने ट्वीट किया, किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी। उन्हें ठेके पर खेती के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा। न दाम मिलेगा, न सम्मान। किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। उन्होंने दावा किया, भाजपा के कृषि विधेयक ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाते हैं। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। भारत बंद का समर्थन करते हुए कांग्रेस महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, पेट में अंगारे और मन में तूफान लिए देश का अन्नदाता किसान और भाग्यविधाता खेत मजदूर भारत बंद करने को मजबूर है। अहंकारी मोदी सरकार को न उसके मन की व्यथा दिखती, न उसकी आत्मा की पीड़ा महसूस होती।

चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में नहीं उठाएगा भारत

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। भारत ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद को वह संयुक्त राष्ट्र के मंच पर नहीं उठाएगा। भारत ने स्पष्ट किया है कि दोनों पक्ष इस विवाद का समाधान द्विपक्षीय बातचीत के जरिये कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी एस तिरुमूर्ति ने एक बयान में कहा कि दोनों देश इतने परिपक्व हैं कि आपसी विश्वास मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के जरिये द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से इसका विवाद का समाधान कर सकते हैं। चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा कराने की भारत मांग करेगा अथवा नहीं इस पर श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि हम इस मुद्दे का समाधान करने के लिए पहले से ही द्विपक्षीय रूप से काम कर रहे हैं। हमारे द्विपक्षीय मामलों में संयुक्त राष्ट्र की कोई भूमिका नहीं हो सकती। दरअसल, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच पिछले करीब चार महीनों से तनाव बरकरार है। इसका समाधान करने के लिए दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री स्तर की मुलाकात से लेकर अब तक कई चरण की बातचीत हो चुकी है। गौरतलब है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता करने के प्रस्ताव को भी यह कहकर ठुकरा दिया था कि इसका समाधान द्विपक्षीय बातचीत के जरिये किया जा सकता है।

शोपियां मुठभेड़ में मारे गए 3 लोगों के डीएनए परिवार के सदस्यों से मिले

श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में जुलाई में सेना के साथ कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए तीन लोगों के डीएनए नमूने राजौरी में उनके परिवारों के नमूनों से मेल खाते हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह पूछे जाने पर क्या वे तीनों वास्तव में मजदूर थे, जैसा उनके परिवारों ने दावा किया है और वे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं थे, पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह आगे की जांच का विषय है। सेना ने 18 जुलाई को दावा किया था कि दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में गांव अमशीपुरा में तीन आतंकवादी मारे गए। सोशल मीडिया की रिपोर्टों से संकेत मिला कि वे राजौरी के रहने वाले तीन लोग अमशीपुरा में लापता हो गए थे। इसके बाद सेना ने जांच शुरू की थी। तीन लोगों के परिवारों ने दावा किया था कि वे मजदूर थे और इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस संबंध में पुलिस ने भी जांच शुरू की और मारे गए लोगों के डीएनए नमूने लिए गए ताकि राजौरी में उनके परिवारों के नमूनों के साथ मिलान किया जा सके। पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) विजय कुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, डीएनए रिपोर्ट आ गई है और मिलान हो गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या इसकी पुष्टि हो गई है कि तीनों लोग मजदूर थे और वे किसी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं थे, कुमार ने कहा, पुलिस अब मामले में आगे की जांच कर रही है। सेना ने रिकार्ड चार सप्ताह में इस मामले की जांच पूरी कर ली। बल ने 18 सितंबर को कहा था कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य के अनुसार मुठभेड़ के दौरान उसके जवानों ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अधिकार का उल्लंघन किया।

दीपिका पादुकोण का ड्रग्स कनेक्शन

जिस वॉट्सऐप ग्रुप में दीपिका ने लिखा था माल है क्या, उसकी खुद ही एडमिन निकलीं

नयी दिल्ली, एजेंसी। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। 2017 के जिस वॉट्सऐप ग्रुप में दीपिका ने 'हैश' (हशीश) और 'माल है क्या?' जैसी लाइन लिखी थी, उस ग्रुप की वह खुद एडमिन थीं। भास्कर को सूत्रों ने बताया कि दीपिका के अलावा उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश और रिया चक्रवर्ती की मैनेजर रहीं जया साहा भी इसकी एडमिन थीं। कुछ महीने पहले ही यह ग्रुप डिलीट किया गया। इस ग्रुप में कई नामचीन सितारे और उनके मैनेजर जुड़े थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को ग्रुप की कई ड्रग चैट मिली हैं, जिसके आधार पर एनसीबी ड्रग सिंडिकेट ऑपरेट करने का केस दर्ज कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, ग्रुप में 12 मेंबर थे। करिश्मा ने पूछताछ में बताया कि वह जाया साहा के अंडर में काम करती थी। दीपिका को लेकर उनसे कई बार बातचीत हुई। जया और दीपिका की मुलाकात भी करिश्मा ने ही करवाई थी। सूत्रों के अनुसार, करिश्मा ने दीपिका के लिए ड्रग्स खरीदने की बात कबूल कर ली है। ग्रुप की चैट से पता चला है कि सेलेब्रिटीज ड्रग्स की खरीदारी अपने स्टाफ या मैनेजर के जरिए करते थे। करिश्मा प्रकाश से एनसीबी से पूछताछ की। उसने ड्रग्स से जुड़े किसी भी मामले में शामिल होने से साफ मना किया है। सूत्रों के मुताबिक, करिश्मा से जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, वह रोने लगी। एनसीबी ने उसके इस ग्रुप में शामिल होने के सबूत रखे तो उसने दीपिका को लेकर कई बड़े खुलासे किए। करिश्मा ने बताया कि इस ग्रुप में दीपिका ने ही उसे जबरन जोड़ा था। ग्रुप में दीपिका और करिश्मा प्रकाश के बीच हुई बातचीत सार्वजनिक हुई थी।

मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रतिवर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देगी सरकारः योगी

लखनऊ, संवाददाता। उत्तरप्रदेश प्रदेश के सूचना विभाग के नये दफ्तर के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों के लिये दो महत्वपूर्ण घोषणाऐं कीं। वरिष्ठ पत्रकार एवं इन्डियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्लूजे) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा० के० विक्रम राव एवं वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर पांडेय की उपस्थिति में ये घोषणा करते हुऐ मुख्यमंत्री ने पत्रकार साथियों का 5 लाख् रू का बीमा एवं कोरोना से मृत्यु पश्चात 10 लाख रू की आर्थिक राशि दिए जाने की बात कही। आईएफडब्लूजे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पत्रकार साथियों को पाँच लाख रू की धनराशि का बीमा व् आकस्मिक निधन पर उनके परिजनों को दस लाख् रू की सहायता राशि व् कोरोना से मृत्यु होने पर दस लाख रू0 दिए जाने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 के विक्रम राव ने बताया कि यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान पत्रकार हित में तमाम मुद्दों को लेकर विस्तार से बातचीत की थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनकी मांग पर पहले ही देश के कई राज्यों की सरकारों ने बीमा व् पत्रकारों के अकस्मात निधन पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दे रखी है। साथ ही उन्होंने सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून, वरिष्ठ पत्रकार साथियों को पेंशन व् पत्रकारों के परिजनों को चिकित्सीय सुविधा भी प्रदान करने की मांग करी। श्री राव ने पत्रकार हित में तमाम मांगो को पुनः दोहराते हुए कहा कि सरकार का दायित्व है कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे चौथे स्तंभ की मूलभूत सुविधाओं के साथ उनके आत्मबल को सरकार मजबूती प्रदान करें। आईएफडब्लूजे की राज्य इकाई उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन (यूपीडब्लूजेयू) के प्रदेश अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा यूनियन की मांगो पर अमल करने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की मांग पर सरकारी सुविधा प्राप्त पत्रकार साथियों के लिए बेहद मददगार साबित होगी। हसीब सिद्दीकी ने कहा कि देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते यहाँ के पत्रकार साथी लंबे समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान का इन्तजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए यह बेहद ही गौरवान्वित करने वाले क्षणों में से एक है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार आगे भी पत्रकार हितों का पूर्ण ख्याल रखे। लखनऊ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के मंडल अध्यक्ष शिव शरन सिंह ने पत्रकार हित में फैसले का ऐलान करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का फैसला पत्रकार साथियों के मनोबल को और ऊंचा करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि यूनियन ने कई बार मांग की है कि किसी भी पत्रकार साथी के निधन पर राज्य सरकार नीति बनाकर एक निश्चित धनराशि पत्रकारों के परिजन को उपलब्ध कराए। साथ ही उन्होंने पत्रकारों को -कोरोना योद्धा घोषित करने व् निजी आवास जैसी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर भी उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री जल्द इन मुद्दों की भी घोषणा कर हमारे पत्रकारों को उत्साहित करने का काम करेंगे।

कांग्रेस ने किसान विरोधी बिल के विरोध में मार्केट को बन्द कराया

लखनऊ, संवाददाता। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने भाजपा सरकार द्वारा पास किये गये किसान विरोधी बिल के विरुद्ध भारत बन्द के आवाह्न किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर किसान संघर्ष समिति के समर्थन में महानगर कांग्रेस कमेटी लखनऊ द्वारा आज बड़ी संख्या में नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ ऐशबाग स्थित हैदरगंज चौराहा मार्केट को बन्द कराया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि भाजपा सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल पास करके हरित क्रांति को विफल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के किसान, खेत और खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षडयंत्र किया है। उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता व भाग्यविधाता किसान तथा खेत मजदूर की मेहनत को केन्द्र सरकार द्वारा चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षडयंत्र किया जा रहा है।

योगी सरकार के निर्देशों के बावजूद दलितों व महिलाओं पर अत्याचार जारीः मायावती

लखनऊ, संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की अनंत घोषणाओं और निर्देशों के बावजूद दलितों और महिलाओं के खिलाफअपराधों में कमी नहीं आई है। मायवती ने ट्वीट किया, यूपी सरकार की अनंत घोषणाओं व निर्देशों आदि के बावजूद दलितों व महिलाओं पर अन्याय-अत्याचार, बलात्कार व हत्या आदि की घटनाएं नहीं रूक रही हैं तो इससे सरकार की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। खासकर छात्राओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है तो ऐसी कानून-व्यवस्था किस काम की।

सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित, राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक देशद्रोह के बराबर

लखनऊ, संवाददाता। देश के नागरिकों के खिलाफसभी अधिकारों से वंचित करना और उन्हें संविधान और न्याय से वंचित करना एक तरह का राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वासघात है और अपराधियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करके कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यह बात सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संयोजक मुहम्मद अफाक ने आज यहां पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा, हमारे कई राजनेता और नौकरशाह भी लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफकाम करते हैं, जिस पर मुकदमा चलना चाहिए, भले ही इसका मतलब गरीबों को शिक्षा से वंचित रखना हो, उन्होंने कहा। चाहे उन्हें उनकी नौकरियों से वंचित करना हो, या उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें अवैध रूप से परेशान करना हो, वे तब तक गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों का समान रूप से शोषण करते रहेंगे जब तक कि उनके खिलाफराष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जाती। रोक के लिए सख्त सजा मिलनी चाहिए।

कोतवाली मुगलसराय की वसूली लिस्ट- 35.64 लाख, प्रति माह

लखनऊ, संवाददाता। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने थाना कोतवाली मुगलसराय, चन्दौली की कथित वसूली लिस्ट बताई गयी जाँच की मांग की है, डीजीपी यूपी एच सी अवस्थी को भेजे अपने पत्र तथा ट्वीट में अमिताभ ने इस कथित वसूली लिस्ट को संलग्न करते हुए कहा कि उन्हें दी गयी जानकारी के अनुसार यह थाना कोतवाली मुगलसराय, चंदौली की वसूली लिस्ट बताई गयी है. इस हैण्डरिटेन लिस्ट से टोटल प्रति माह की वसूली रु0 35.64 लाख के अलावा 15 व्यक्तियों से अवैध खनन से रु0 12500 प्रति वाहन तथा पडवा कट्टा का काम करने वाले कबाड़ी से रु0 4000 प्रति वाहन होता है. इसमें संजय जायसवाल तथा दीपक जायसवाल से गांजा दूकान का रु0 25 लाख भी शामिल है, अमिताभ ने कहा कि इस लिस्ट में तमाम नाम व कई सारे डिटेल्ड फैक्ट्स अंकित हैं, जिन्हें प्राथमिक स्तर पर खुले एवं गोपनीय जाँच द्वारा सत्यापित किया जा सकता है,उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस लिस्ट में अनेकानेक व्यक्तियों के नाम, उनके व्यवसाय तथा उनसे हुई कथित वसूली का उल्लेख है, इन तथ्यों की गहन जाँच जरुरी है।

मुम्बई के लिए तीन स्पेशल ट्रेनें 28 सितंबर से

लखनऊ, संवाददाता। मुम्बई जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पूर्वोत्तर रेलवे मुम्बई के लिए तीन और स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। 28 सितंबर से चलने वाले ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पीके सिंह ने बताया कि मुंबई के लिए पूर्व से चलाई जा रही ट्रेनों के अतिरिक्त तीन और ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेनें गोरखपुर से चलकर लखनऊ के रास्ते मुम्बई के बीच आवागमन करेंगी। ट्रेनों में आरक्षण 26 सितंबर से शुरू होगा। पहली ट्रेन नंबर 05063 गोरखपुर एलटीटी साप्ताहिक ट्रेन 28 सितंबर से हर सोमवार को गोरखपुर से तड़के साढ़े पांच बजे चलकर उसी दिन दोपहर 2.20 बजे लखनऊ जंक्शन और अगले दिन शाम चार बजे एलटीटी पहुंचेगी। वापसी में 05064 हर मंगलवार को एलटीटी से शाम 5.50 बजे चलकर अगले दिन शाम 7.55 बजे लखनऊ व तड़के 4.30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

मुख्यमंत्री ने कानपुर नगर और लखनऊ में अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों की तैनाती करते हुए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के दिए निर्देश

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कानपुर नगर और लखनऊ में अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों की तैनाती करते हुए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आर0एम0एल0आई0एम0एस0 में उपलब्ध 300 बेड्स के भवन को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कोविड अस्पतालों में सभी औषधियों एवं अन्य मेडिकल सामग्री की सुचारु उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से जनपद स्तर पर संवाद के साथ-साथ सी0एम0 हेल्पलाइन के माध्यम से भी सम्पर्क स्थापित रखते हुए उनके स्वास्थ्य की नियमित जानकारी प्राप्त की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा मेडिकल टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इनसे जुड़ी कार्यवाही को पूरी तेजी से संचालित किया जाए। कॉन्टैक्ट टेऊसिंग को गति प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त टीमें लगाई जाए। ज्यादा से ज्यादा मेडिकल टेस्टिंग करने के लिए सभी लैब्स को पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से बचाव और सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता का अभियान जारी रखा जाए। इसके लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों के साथ-साथ पब्लिक एडेऊस सिस्टम का व्यापक तौर पर उपयोग किया जाए। पब्लिक एडेऊस सिस्टम के द्वारा लोगों को कोविड-19 से सुरक्षा तथा यातायात नियमों की जानकारी दी जाए। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उप्र का किसान इतना सादा (सीधा) नहीं कि वह अपना नफा-नुकसान न समझता हो

लखनऊ, संवाददाता। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि संसद में बगैर चर्चा और प्रक्रिया अपनाये ही तानाशाही तरीके से तीन कृषि कानून 1.कृषि उपज, व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2.मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर किसान समझौता 3.आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक(अनाज, दालें, खाद्य तेल, आलू, प्याज यह अनिवार्य वस्तु नहीं मानी जाएगी।) पारित करने से मोदी सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। खुद को किसान हितैषी बताने वाली मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों की आय को दुगुना करने का संकल्प लिया था किन्तु 6 साल में भाजपा के शासनकाल में कृषि ग्रोथ जहां 3.1 प्रतिशत है वहीं यूपीए शासनकाल में 4.3 प्रतिशत थी। कृषि आय 14 साल में इस साल सबसे कम है। किसान की उपज का दाम पिछले 18 साल में इस साल सबसे कम आया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे लेकिन उसे लागू न करके किसानों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होने कहा कि उपरोक्त तीनों नये कृषि कानूनों में एम0एस0सी0 का जिक्र न किये जाने से -सरकारी अनाज मंडिया सब्जी तथा फल मंडिया समाप्त हो जायेंगी जिसकी वजह से किसान पूंजीपतियों द्वारा तय किये गये मूल्य पर अपने उत्पादित फसल को बेंचने के लिए बाध्य हो जाएगा। अनाज मण्डी, सब्जी व फल मण्डी खत्म करने से कृषि उपज व्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी और पूंजीपतियों को फायदा होगा। सीएसीपी(कमीशन फार एग्रीकल्चरल कास्ट एण्ड प्राइसेस) आयोग जो भारत सरकार को कृषि उपज के दाम का निर्धारण करती है उसने सिफारिश की है कि किसानों को इस वर्ष मंहगाई 8.6प्रतिशत हो गयी है इसलिए गेहूं की एमएसपी पर 6.6 प्रतिशत और धान पर 5.9 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की जाए किन्तु अफसोस यह है कि गेहूं में 2.6 प्रतिशत और धान पर 2.9 प्रतिशत बढ़ाया है और संसद में घोषणा किया कि 50 रू0 प्रति कुन्तल बढ़ा दिया। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि जिन भी कृषि उपज गेहूं, धान, मक्का, सरसों आदि का एमएसपी पर खरीद होती है इसका रिव्यू किया जाए। इसके साथ ही उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में 5000रू0 प्रति किसान दिया जाए। उन्होने कहा कि भारत सरकार कुछ किसानों के खाते में 500रू0 प्रतिमाह यानि 6000रूपये वार्षिक देकर डीजल पर जो एक्साइज यूपीए शासनकाल में 3.56 पैसे था उसे बढ़ाकर 40 रूपये कर दिया है जिससे किसानों को सिर्फ डीजल खरीद में 6000रू0 सालाना अधिक देना पड़ रहा है। उन्होने कहा कि किसानों की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि आज देश में हर घंटे पर एक किसान आत्महत्या करने को विवश है।

किसान बिल अध्यादेश के विरोध में पूरे देश में किसानों ने किया चक्का जाम

लखनऊ, संवाददाता। किसान बिल अध्यादेश के विरोध में आज पूरे देश में किसानों ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इस क्रम में लखनऊ के मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब, एनएच 24 किसान यूनियन ने चक्का जाम किया। इस दौरान लखनऊ-बाराबंकी बॉर्डर पर किसानों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। एनएच 24 हाईवे रोड ब्लॉक से सैंकड़ों वाहनों का लगा लंबा जाम भारतीय किसान यूनियन के आवाहन पर पूरे देश में चक्का जाम 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा पास किया गया किसान अध्यादेश, किसान विरोधी है इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। इसी को लेकर आज पूरे देश के किसान सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान किसानों ने 'मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जो किसान की बात करेगा वह दिल्ली पर राज करेगा, अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जौनपुर तथा देवरिया की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद जौनपुर तथा देवरिया की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जनपद जौनपुर की लगभग 36 करोड़ 47 लाख रुपए की कुल लागत की 36 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा लगभग 91 करोड़ 70 लाख रुपए की कुल लागत की 44 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने जनपद देवरिया की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। यह परियोजनाएं लगभग 82 करोड़ 33 लाख रुपए की धनराशि से निर्मित की गई है। उन्होंने 131 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनके निर्माण पर 382 करोड़ 84 लाख रुपए से अधिक धनराशि व्यय होगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनपद जौनपुर तथा देवरिया के विकास से जुड़ी अनेक घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कलीचाबाद में गोमती नदी पर पुल के निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि यह पुल राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे के नाम पर निर्मित किया जाएगा। इसके अलावा सिकरारा से शेरवां सड़क का उच्चीकरण करते हुए इसका नामकरण वैज्ञानिक श्री लालजी सिंह के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने निषादराज राजकीय बलिका इण्टर कॉलेज की घोषणा भी की है। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकरारा को 100 बेड का अस्पताल बनाने एवं इसका नामकरण वैज्ञानिक लालजी सिंह के नाम पर करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जनपद देवरिया में दिवंगत विधायक जन्मेजय सिंह की स्मृति में एक पार्क का नामकरण किया जाएगा। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम सेनानी शहीद रामचन्द्र विद्यार्थी के नाम पर एक संग्रहालय तथा स्वाधीनता संग्राम सेनानी शहीद सोना सोनार के नाम पर गण्डक नदी पर एक पुल का निर्माण कराए जाने की घोषणा भी की।

शांति पूर्वक निपटी परीक्षा पॉलिटेक्निक के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा

लखनऊ, संवाददाता। पॉलिटेक्निक के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा शुक्रवार को शांतिपूर्वक निपटी। पहली बार विभाग ने 186 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन पेपर पहुंचाया। पेपर पहुंचाने में एकेटीयू ने भी तकनीकी मदद की। परीक्षा शांतिपूर्वक निपटने पर विभाग ने राहत की सांस ली है। पॉलिटेक्निक के अंतिम सेमेस्टर की वार्षिक परीक्षाएं 25 सितंबर से शुरू हुईं। जो 12 अक्टूबर तक चलेंगी। परीक्षा में करीब 75000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। पहली बार विभाग ने ऑनलाइन पेपर भेजने की कवायद की थी। जो सफल हुई है। हालांकि इसे भेजने में कुछ दूसरी संस्थाओं ने भी काफी मदद की है। इसके लिए काफी सतर्कता बरती गई। प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव डॉ आरके सिंह ने प्रश्न पत्रों को भेजने के लिए संस्थाओं में पहले से ही आवश्यक उपकरणों, साज-सज्जा एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई थी।

उत्तर प्रदेश में उजाडे गए पुश्तैनी टिंबर व्यापारियों को सरकार पुन व्यापार करने का मौका दे

लखनऊ, संवाददाता। फेडरेशन ऑफ आल इंडिया व्यापार मंडल (फैम) ,उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार से मांग की है कि 2017 में उत्तर प्रदेश के उजाडे गए पुश्तैनी व पुराने टिंबर व्यापारियों को नई नीति का गठन या संशोधन कर पुनः व्यापार करने का मौका दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ को लिखे पत्र में , फैम ने लिखा है उत्तर प्रदेश में आरा मशीनें, प्लाईवुड व विनियर एक परंपरागत लघु उद्योग रहा है एवं लाखो परिवार अपने इस पुश्तैनी व्यापार से जुड़ कर अपना एवं अपने परिवारों एवं अपने कर्मचरियो के परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। यह ऐसा व्यवसाय था जो सरकार से किसी भी अनुदान या अनुकम्पा के बिना ही स्वयं अपने हेतु संसाधन जुटा रहा था।फैम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रभारी ,उत्तर प्रदेश लखन लाल गुप्ता ने बताया किअपने पत्र के माध्यम से फैम में मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 2017 में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर वर्षो से चली आ रही पुस्तैनी आरा मशीनें, प्लाईवुड व विनियर के लघु उद्योगों को सरकारी कर्मचारियों द्वारा अचानक उजाड़ दिया गया। इन में से अधिकांशतः मालिकों के पास वन विभाग द्वारा जारी कुछ ई-3 रसीदे, वैध बिजली कनेक्शन व व्यापार संबंधी कानूनी दस्तावेज उपलब्ध भी थे , पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा उन सब को अनदेखा कर इन परंपरागत एवं पुस्तैनी लघु उद्योगों को बंद करवा दिया गया। यह व्यवसाय हस्तकला पर निर्भर था अतः इस कारोबार में रोजगार देने की क्षमता अन्य किसी लघु उद्योगों से ज्यादा थी। आज स्थिति यह है किं आरा मशीनें, प्लाईवुड व विनियर के निर्माता लघु कारोबारी दर दर की ठोकर खा रहे है।

किसानों के सफल प्रतिरोध के लिये वाम दलों ने उन्हें बधाई दी

विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा कर किसानों का अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के वामपंथी दलों ने कहा कि किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का संयुक्त प्रतिरोध आज उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर संपन्न हुआ। किसानो और उनके समर्थक दलों और संगठनों ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर धरने दिये, प्रदर्शन किये, रास्ते जाम किये और सरकार के पुतले फूंके। अनेक जगह किसानों के समर्थन में बाजार भी बन्द हुये। उत्तर प्रदेश के वामपंथी दलों ने इस अभूतपूर्व कार्यवाही के लिए उत्तर प्रदेश और देश के किसानों, मजदूरों, युवाओं एवं छात्रों को बधाई दी है। वामपंथी पार्टियों, उनके सहयोगी मजदूर, छात्र और नौजवान संगठनों ने भी इस कार्यवाही में बड़े पैमाने पर भाग लिया और सरकार को उसके कुकृत्यों पर आईना दिखाया। वामपंथी दलों का आरोप है कि किसान विरोधी इन काले कानूनों का हमला देश के 90 प्रतिशत किसान झेल नहीं पायेंगे। अपनी उपजों की कीमतों के लिए वे कारपोरेट घरानों के सामने घुटने टेकने और अंततः अपनी जमीनों को कार्पोरेट्स के आगे सरेंडर करने को मजबूर होंगे। ये विशाल किसान समुदाय को मजदूर बनाने की साजिश है। ये मंडी समितियों की खरबों रुपये की संपत्ति को कार्पोरेट्स के ऋषि माल्स के लिये सौंपने की तैयारी है। यह कथित राष्ट्रवादियों का विश्व व्यापार संगठन और बहुराष्ट्रीय निगमों के सामने शर्मनाक सरेंडर है। वामपंथी दलों ने कहा कि प्रधानमंत्री विपक्षी दलों पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा कर किसानों का अपमान कर रहे हैं। सरकार की नीतियों से खोखले बनने से क्षुब्ध किसान जब प्रतिरोध कर रहे हैं तो पीएम उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। यह आपत्तिजनक भी है और निंदनीय भी। वामपंथी दलों ने किसान कार्यवाहियों को पुलिस बलों के बल पर बाधित करने का आरोप भी लगाया। उन्होने देश में कई जगह किसानों पर संघियों के संगठित गिरोहों के हमलों की भी निन्दा की। वामपंथी दलों ने देश के राष्ट्रपति से मांग की कि वे किसान हित में काले कानूनों पर हस्ताक्षर न करें। अन्यथा यह प्रतिरोध शायद ही थमेगा। उपर्युक्त बयान भारत की कम्युनिस्ट पार्टी- मार्क्सवादी के राज्य सचिव डा? हीरालाल यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी- माले के राज्य सचिव का? सुधाकर यादव, फारबर्ड ब्लाक के राज्य संयोजक अभिनव कुशवाहा एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव डा? गिरीश ने जारी किया है।

प्रदेश में अब तक कुल 93,10,258 सैम्पल की जांच की गयी

24 घंटें में कोरोना के संक्रमित 4519 नये मामले आये सामने

लखनऊ, संवाददाता। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,64,742 सैम्पल की जांच की गयी। प्रदेश में अब तक कुल 93,10,258 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटें में कोरोना के संक्रमित 4519 नये मामले आये है। प्रदेश में अब तक कुल 3,13,686 लोग पूर्णतया उपचारित होकर डिस्चार्ज किये गये। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 6075 लोग

उपचारित हुए। प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर 82.86 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 59,397 कोरोना के एक्टिव मामले है। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन में 30,331 लोग हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में सरकारी कार्यालयों एवं महत्वपूर्ण संस्थानों में 64,507 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किये जा चुके है। इनके माध्यम से 7,85,986 लोगों का लक्षणात्मक चिन्हांकन किया गया है। निजी चिकित्सालयों में 3697 लोग तथा सेमी पेड एल-1 प्लस में 144 लोग ईलाज करा रहे है। उन्होंने बताया कि नॉन कोविड केयर के अन्तर्गत पिछले वर्ष 01-24 सितम्बर तक सरकारी चिकित्सालयों में मेजर आपरेशन 16,943 हुए जबकि इस वर्ष इसी अवधि में 12,247 मेजर आपरेशन हुये है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करोना का ग्राफ डिकलाइन होने लगा है।

खेती को तबाह कर देगा कृषि विधेयकः मजदूर किसान मंच

लखनऊ, संवाददाता। मोदी सरकार के किसान विरोधी विधेयकों के खिलाफ अखिल भारतीय किसान मजदूर संघर्ष समन्वय समिति के आव्हान पर आज मजदूर किसान मंच ने उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू किया. सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, सीतापुर, आगरा, लखीमपुर खीरी, हरदोई, जौनपुर, वाराणसी, बाराबंकी, गोंडा आदि जिलों में गांव-गांव किसानों, मजदूरों और आदिवासियों ने मोदी सरकार और अध्यादेशों का पुतला फूंक के अपना विरोध व्यक्त किया. प्रदेश में इलाहाबाद समेत कई जनपदों में युवा मंच के कार्यकर्ता भी इन विरोध प्रदर्शनों में किसानों के समर्थन में उतरे. ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व आईजी एस. आर. दारापुरी व मजदूर किसान मंच के महासचिव डा. बृज बिहारी ने किसानों को सफल आंदोलन के लिए बधाई देते हुए जारी बयान में कहा कि मोदी सरकार वित्तीय पूंजी की चाकरी में लगी हुई है और लगातार किसान, मजदूर, नौजवान विरोधी कार्रवाई कर रही हैं।

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल का किया विरोध, सौंपा ज्ञापन

लखनऊ, संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार जिला,महानगर समाजवादी पार्टी लखनऊ ने किसानों एवं श्रमिकों के हितों पर आघात पहुंचाने वाले कृषि एवं श्रम कानूनों के विरोध में जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट पर सौंपा। किसानों के हितों की अनदेखी करने वाला जो कृषि विधेयक भारत सरकार लाई है, उससे किसान अपनी जमीन का मालिक न रहकर मजदूर हो जायेगा। कृषि उत्पादन मण्डी की समाप्ति और विधेयक में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित न होने से किसान अब औनेपौने दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हो जायेगा। गेहूं, धान की फसल को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटाये जाने से किसान को बड़े आढ़तियों और व्यापारियों की शर्तों पर अपनी फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा। संसद से पारित श्रमिक कानून से श्रमिकों के हित बुरी तरह प्रभावित होंगे। इन जनविरोधी कानूनों को लेकर किसानों में भारी आक्रोष व्याप्त है, जिस कारण किसान जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है, उल्टे श्रमिकों को पूंजीपतियों की दया पर आश्रित बनाने की साजिष की जा रही है। केन्द्र और प्रदेश की सरकारों की जनविरोधी नीतियों से किसान और श्रमिकों के हितों को गहरा आघात लगा है। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष जयसिंह 'जयन्त', महानगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित, जिला महासचिव शब्बीर अहमद खान, महानगर महासचिव सौरभ यादव, लखनऊ बार एसोसिएशन महामंत्री जीतू यादव, जिलाध्महानगर उपाध्यक्ष मान सिंह वर्मा, नवनीत सिंह, ताराचन्द्र यादव, नवीन धवन बन्टी, मीडिया प्रभारी रमेश सिंह 'रवि', अधिवक्ता सभा जिलाध्यक्ष अंजनी प्रकाश यादव, महासचिव सिद्धार्थ आनन्द, सिकन्दर यादव मौजूद रहे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पी. एम. आवास लाभार्थियों के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल

लखनऊ, संवाददाता। भाजपा लखनऊ महानगर द्वारा सरोजनीनगर विधानसभा में राजा बिजली पासी द्वितीय वार्ड के छुहारा खेड़ा में प्रधानमंत्री आवास एवं शौचालय लाभार्थियों के मध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, क्षेत्रीय विधायक, और ऐसी विचार धारा को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई जी ने बढ़ाया जिसको वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस और शौचालय किसानों के लिए किसान सम्मान निधी के रूप में प्रति वर्ष छः हजार रुपए देने का काम जैसी अनेकों योजनाओं को लागू करने का काम किया है।

जिलाधिकारी ने कम सैम्पलिंग वाले चिकित्सा संस्थान को नोटिस देने का दिया निर्देश

बस्ती। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों के नजदीकी लोगों की समय से पहचान न किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होने इस संबंध में संक्रमित लोगों की सूची पुलिस अधीक्षक को भेजवाने का निर्देश दिया है ताकि थानों के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान कर उनका टेस्ट कराया जा सकें। विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में उन्होने कहा कि संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आये लोगों से वायरस फैलने की पूरी सम्भावना रहती है।

उन्होने निर्देश दिया कि अन्टेऊस के बारे में संबंधित एसडीएम तथा सीओ को सूचना तत्काल भेजनी चाहिए, जो एकीकृत कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेण्टर (आईसीसीसी) द्वारा नही किया गया। अन्टेऊस केस नूर हास्पिटल का है जहॉ पर उसकी एन्टीजन जॉच करायी गयी थी। इस संबंध में लापरवाही बरतने पर हास्पिटल को नोटिस भेजवाने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि 06 अन्य केस दूसरे जिलो के है, जो अन्टेऊस है। इसमें से दो-दो बहराईच एंव पीजीआई लखनऊ, एक-एक केस अयोध्या एवं सिद्धार्थ नगर का होना बताया गया है। इसमें से एक केस की जॉच सीएचसी मरवटिया में एन्टीजन से हुयी थी और वे सिद्धार्थ नगर चले गये। जिलाधिकारी ने इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होने सीएमओ को निर्देश दिया कि दूसरे जनपदों के लोगों की अपने जिले में एन्टीजन जॉच न करायी जाय। उन्होने

कहा कि एन्टीजन जॉच कराने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड एंव मोबाईल नम्बर अवश्य लिया जाय। उन्होने कहा कि ऐसे केस जो जॉच के बाद अपने जिलों में चले जाते है उनके पॉजिटिव पाये जाने पर या मृत्यु होने पर असहज स्थिति होती है। इसका कड़ाई से पालन कराये। सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि गुरूवार को सायं 04.00 बजे आईसीसीसी में कोई अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित नही था। यह बहुत गम्भीर स्थिति है। उन्होने निर्देश दिया कि आईसीसीसी में तैनात सभी अधिकारी-कर्मचारी समय से ड्यिूटी पर आये और पूरे समय उपस्थित रहें। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि दोनो शिफ्ट में कोई डिप्टी सीएमओ थोड़ी देर के लिए यहॉ अवश्य उपस्थित रहें। प्राचार्य मेडिकल कालेज डॉ0 नवनीत कुमार ने बताया कि ओपेक हास्पिटल कैली से ठीक हुये मरीजों को पोर्टल पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है परन्तु जहॉ से रेफर हो कर मरीज आता है, संबंधित चिकित्सालय द्वारा पोर्टल पर डिस्चार्ज नही किया जाता है। ऐसी स्थिति में कैली से डिस्चार्ज मरीज पोर्टल पर भर्ती रहना प्रदर्शित होता है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि संबंधित जनपद के सीएमओ से बात करके पोर्टल पर सूचना ठीक कराये। बैठक में फैसिलिटीवार डिस्चार्ज मरीजो की समीक्षा की गयी। गुरूवार को 23 होमआईशोलेसन वाले मरीज भी डिस्चार्ज हुए है। जिलाधिकारी ने कैली अस्पताल में भर्ती गम्भीर रोगों के मरीजो की समीक्षा की गयी। यहॉ पर 03 ऐसे मरीज भर्ती है जो कोरोना निगेटिव हो गये है लेकिन गम्भीर बीमारी के कारण आक्सीजन पर है। कुछ महत्वपूर्ण दवाओं की अनउपलब्धता के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसकी सूची ड्रग इन्स्पेक्टर को उपलब्ध करा दें। वे दवाओं के दुकान पर इसकी उपलब्धता करा देंगे। बैठक में सैम्पलिंग की समीक्षा की गयी। शासन के निर्देशानुसार प्रतिदिन 1500 एन्टीजन तथा 450 एनटीपीसीआर से जॉच के निर्देश है। गुरूवार को 1000 सैम्पलिंग की सूचना है। सैम्पलिंग कम होने का कारण बारिश का होना बताया गया। जिलाधिकारी ने कम सैम्पलिंग वाले चिकित्सा संस्थान को नोटिस देने का निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय पोषण माह को सफल बनाने के लिए आगे आयें स्काउट गाइडःसीडीओ

बस्ती। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए स्काउट गाइड आगे आएं और कुपोषण से होने वाली बीमारियों से किशोरियों एवं महिलाओं को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना सुनिश्चित करें, यह विचार मुख्य विकास अधिकारी हरनीत कौर रोका ने विकास भवन में व्यक्त किया कहा कि बालिकाओं एवं महिलाओं को कुपोषण से होने वाली समस्याओं से बचाने के लिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा इसी क्रम में हम सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कुपोषण के खिलाफ जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना सुनिश्चित करें। इस दौरान जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट कुलदीप सिंह ने अपने विचार रखते हुए कहा कि स्काउट गाइड नुक्कड़ नाटक के जरिए पोषण की महत्ता को आमजन तक पहुंचाने एवं कुपोषण से होने वाले समस्याओं के प्रति सभी को जागरूक करेंगे। रोटरी क्लब अध्यक्ष डॉ डीके गुप्ता, इनरव्हील क्लब अध्यक्ष डॉ निधि गुप्ता रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव सरदार कुलविंदर सिंह ने अपने अपने विचार रखे।

लड़की की माँ ने लगाया छेड़खानी का आरोप

थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह ने तत्परता दिखाते हुए प्रमोद सिंह को किया गिरफ्तार

गोरखपुर/गोरखनाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली रेनू तिवारी निवासी नियर शनिमंदिर हुमांयुपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ ने आरोप लगाया है। कि संगम स्वीट के मालिक प्रमोद सिंह ने उनकी लड़की के साथ कल दिनांक 24.09.2020 को उस वक्त छेडख़ानी की जब वो दुकान पर समान लेने के लिए गयी थी। आज दिनांक 25.09.2020 समय करीब 10 बजे लड़की की माँ और परिवार के 4 लोग प्रमोद सिंह की दुकान पर पहुचे और मारने पीटने लगें किसी ने मारपीट का वीडियो बना कर वायरल कर दिया। थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह को वादिनी ने थाने पर आकर तहरीर दिया। गोरखनाथ थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह ने तहरीर मिलते ही प्रमोद सिंह के उपर मुकदमा लिख कर उसको गिरफ्तार कर लिया। प्रमोद सिंह भी उसी मोहल्ले के रहने वाले है। उनकी उम्र करीब 62 वर्ष है जब प्रमोद सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रेनू तिवारी का बकाया था। 546 रुपये जिसको मांगने पर मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगाया गया है। मैंने कोई छेड़खानी नही किया है थाना प्रभारी से पूछा गया है कि जिन लोगो ने सड़क पर मारपीट किया है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे है तो उन्होंने कहा है कि तहरीर मिलने पर उन लोगो के खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाएगा।

कर्मचारियों ने वेतन ना मिलने पर किया अनिश्चित काल तक हड़ताल

महराजगंज। नगर पालिका परिषद नौतनवा के कर्मचारियों ने अधिशासी अधिकारी नौतनवा को अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा लिखित ज्ञापन। जिसमें कर्मचारियों ने मुख्य रूप से अपने बकाया धनराशि का मांग किया है एवं साथ ही साथ सरकार के आदेश अनुसार व नगरपालिका के नियमावली के तहत कर्मचारियों से 8 घंटे का कार्य एवं उनके ड्यूटी के समय ही उनसे व्यवस्था अंतर्गत कार्य लिए जाएं इसकी भी मांग की है। साथ ही साथ नगर पालिका के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों का मरम्मत एवं कर्मचारियों को वर्दी दी जाने की मांग की है जिससे कि उनकी सुरक्षा बनी रहे। अपने सभी मांगों को लेकर नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने नगरपालिका कार्यालय के अंदर ही हड़ताल पर बैठ गए एवं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं वह अनिश्चितकाल तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इस दौरान मौके पर उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजेश बॉयड, जिला उपाध्यक्ष गोविंद प्रसाद, जिला महामंत्री श्रवण कुमार, कोषाध्यक्ष सत्य प्रकाश, दिलीप प्रजापति, संतोष कुमार, रामाशंकर सिंह व संगठन के सभी पदाधिकारी व कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

बारिश ने मचाई तबाही, सीमावर्ती क्षेत्र के कई गांव हुए जलमग्न घरों में घुसा पानी

महराजगंज किसानों के खड़ी फसल हुए बर्बाद, लाखो की हुई क्षति महराजगंज !नेपाल व भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में तीन दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण सड़को सहित पूरा खेत पानी में जल मग्न हो गया है जिसके कारण भारतीय किसानों का पूरा फसल बर्बाद हो गया है। खबरो के अनुसार तीन दिन से नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र व सीमावर्ती इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है जिसके कारण सीमा से सटे रोहिणी नदी चंदन नदी और झरही नदी का जलस्तर बढ़ जाने से नदी का बांध टूट गया है और नदी के पानी से आसपास के कई गांवों की सड़कें पुरी तरह से जलमग्न हो गई है ,फसल पुरी तरीके से डूब गई है, जलस्तर लगातार बढ़ने से पानी घरों में घुसने को आतुर है, जिसके कारण सभी लोग भयभीत है। फसल डूबने से किसान हुए परेशान,लाखो की क्षति का अनुमान एक तरफ लगातार बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है लोग भयभीत है कि कहीं यह पानी उनके घरों में न घुस जाए क्योंकि पानी का स्तर उनके घर के मुहाने पर दस्तक दे चुका है। लेकिन इस समय बड़ी चिंता किसानों के लिए हो गया है क्योंकि उनके धान का खड़ी फसल पुरी तरह डूब गया है ,फसल पक गया था लेकिन बारिश ने फसल की बर्बादी तय कर दिया है, जिससे किसान बहुत ही चिंतित और परेशान है।

प्रधानाध्यापिका हत्याकांड में पुलिस ने एक संदिग्ध को उठाया

गोरखपुर /शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसारथपुर में प्रधानाध्यापिका निवेदिता उर्फ डेविना की गोली मारकर हत्या और बेटी को घायल करने वाले बदमाश के बारे में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। घटना में तिवारीपुर क्षेत्र के रहने वाले बदमाश के शामिल होने का सुराग मिलने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है। अस्पताल में भर्ती निवेदिता की बेटी डेल्सिया का बयान लेने पुलिस की एक टीम लखनऊ गई है। उसकी हालत में सुधार है। इस प्रकरण में पुलिस अब तक 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस का दावा है कि घटना में शामिल एक युवक की पहचान हो गई। एक संदिग्ध को पकड़ भी लिया गया है। शाहपुर पुलिस ने शनिवार को पूर्व पार्षद के भाई व हिरासत में लिए गए एक युवक को छोड़ दिया। तीन दिन से उससे पूछताछ चल रही थी। पूर्व पार्षद के भाई ने निवेदिता से 2.40 लाख रुपये उधार लिए थे। पुलिस को उन्होंने दो लाख रुपये लौटाने का प्रमाण दिया। कॉल डिटेल को खंगालने के बाद हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में भी कोई जानकारी नहीं मिली। तिवारीपुर के रहने वाले बदमाश के शामिल होने की बात सामने आने पर पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में जुटी है। संदेह के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। डेल्सिया ने पुलिस को बताया कि गोली मारने वाले बदमाश सामने से आए थे। राजीवनगर कॉलोनी में मोड़ पर घेरने के बाद गोली मार दी। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस को उसने बदमाशों का हुलिया भी बताया। 20 सितंबर को बदमाशों ने शाहपुर क्षेत्र में प्रधानाध्यापिका निवेदिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उनकी बेटी डेल्सिया घायल हो गई थी। उसका लखनऊ में उपचार चल रहा है।

डीएम की अध्यक्षता में पंचायत भवन निर्माण और सामुदायिक शौचालय निर्माण की हुई समीक्षा

खराब प्रगति वाले सचिवों के विरुद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

बस्ती। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन की अध्यक्षता में पंचायत भवन निर्माण और सामुदायिक शौचालय निर्माण की समीक्षा विकास भवन सभाकक्ष में की गई। पंचायत भवन निर्माण की समीक्षा के दौरान उन्होने पाया कि 758 लक्ष्य के सापेक्ष 604 पंचायत भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो पाया है। पूछ-ताछ करने पर अनारम्भ कार्यो के बारे में इसका स्पष्ट कारण खंड विकास अधिकारी अथवा एडीओ पंचायत नहीं बता पाये। उनके द्वारा बताया गया कि शेष कार्यों में इसलिए प्रारंभ नहीं कराया गया है कि वहां जलजमाव है अथवा भूमि विवाद है।

जिलाधिकारी ने सबसे खराब प्रगति वाले कुदरहा-03, परसरामपुर-06 तथा हरैया 13 पंचायत भवन प्लिंथस्तर की स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई और दिनांक 28.09.2020 तक कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी को कार्यवाही प्रस्तावित करने का निर्देश दिया। संबंधित खंड विकास अधिकारीगण को अपने खराब प्रगति वाले सचिवों के विरुद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। प्रारंभ निर्माण कार्यों में से 313 पर ही प्लिंथ स्तर तक का कार्य पूर्ण हुआ है।

इसी प्रकार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की समीक्षा के दौरान पाया गया कि 1167 की स्वीकृति के सापेक्ष 911 का ही मस्टर रोल जारी हुआ है। इस पर जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित खंड विकास अधिकारियों को सतत निगरानी करने का निर्देश दिया। प्लिंथ स्तर तक के निर्माण कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि मात्र 530 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण प्लिंथ स्तर तक पूर्ण हो पाया है। समीक्षा में विकासखंड दुबौलिया, रुधौली, साऊघाट और कुदरहा की स्थिति सबसे खराब पाई गई। जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए इन विकास खंडों को सुधार के लिए भी दिनांक 28 सितंबर 2020 की तिथि नियत की गई है। यदि 28 तारीख तक अपेक्षित प्रगति नहीं होती है तो जिला पंचायत राज अधिकारी संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने खंड विकास अधिकारियों को सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन के निर्माण की स्वयं दैनिक समीक्षा करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक का संचालन डीपीआरओ विनय सिंह ने किया। बैठक में पीडी आरपी सिंह, समस्त खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत एवं डीसी स्वच्छ भारत मिशन उपस्थित रहे।

गांव के मुख्य मार्ग पर भरा पानी राहगीरों का आवागमन बाधित

महराजगंज। नौतनवां क्षेत्र के ग्राम सभा शिवपुरी के मुख्य मार्ग पर पानी भर जाने से ग्राम वासियों सहित राहगीरों को आने जाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सेखुआनी से शिवतरी जाने वाले मुख्य मार्ग पर करीब 50 मीटर दूरी तक पानी बहने के कारण राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में रोड के ऊपर से बहाव होने के कारण राहगीरों को रोड का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो गया है। वहीं आपको बता दें कि रोड में जगह-जगह गड्ढे हो जाने के कारण राहगीर परेशान दिख रहे हैं ऐसे में लोगों को चोटिल होने का प्रबल बना हुआ है।

05 दिन 06 घण्टे के मानक के आधार पर जिले के सभी 273 स्वास्थ्य उप केन्द्र संचालित करने का दिया निर्देश:जिलाधिकारी

पुलिस लाईन सभागार में आयोजित हुई समीक्षा बैठक

बस्ती। 05 दिन 06 घण्टे के मानक के आधार पर जिले के सभी 273 स्वास्थ्य उप केन्द्र संचालित करने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है। पुलिस लाईन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होने कहा कि एक सप्ताह के भीतर तैयारी पूरी करते हुए 01 अक्टूॅबर से सभी केन्द्र संचालित किए जाय।

उन्होने कहा कि जिले स्तर पर एक कोर कमेटी गठित करके सभी केन्द्रों की प्रतिदिन रिपोर्ट प्राप्त की जाय, जो उन्हें प्रत्येक साप्ताह सोमवार को उपलब्ध कराया जाय। उन्होने कहा कि एक सप्ताह के भीतर सभी स्वास्थ्य उप केन्द्र पर अनउपलब्ध सुविधाए उपलब्ध करायी जाय। उप केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए हैण्डवास, सेनिटाईजेशन की व्यवस्था की जाय। उन्होने कहा कि ये स्वास्थ्य उप केन्द्र न केवल स्वास्थ्य सुविधाए लोगों को उपलब्ध करायेंगी बल्कि जन जागरूकता का कार्य भी करेंगी। प्रतिदिन की मानीटरिंग के आधार पर उप केन्द्र का ग्रेड़िंग किया जायेंगा तथा ए0एन0एम0, आशा एवं संगिनी के क्रियाकलापों का अनुश्रवण करके इनकी रैंकिंग की जायेंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उप केन्द्र सप्ताह में 05 दिन अवश्य खुले तथा प्रतिदिन 06 घण्टे की सेवाए उपलब्ध करायी जाय। उन्होने कहा कि यह संतोष की बात है कि सभी उपकेन्द्र पर ए0एन0एम0 तैनात है। क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं जनजागरूकता के अभियान को गति प्रदान करने में स्वास्थ्य उपकेन्द्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है और इससे जिले में स्वास्थ्य सेवाए बेहतर होंगी। जिला समन्वयक राजेश पाण्डेय ने बताया कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण उनकी जॉच, आरसीएच पोर्टल पर पंजीकरण, शतप्रतिशत प्रसव, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का लाभ दिलाना, पात्र दम्पति का पंजीकरण करना, नवजात शिशु की देखभाल, कुपोषित बच्चों को एनआरसी भेजना, परिवार नियोजन, अन्तराल दिवस का आयोजन, नसबन्दी, गैर संचारी रोग कार्यक्रम, किशोर स्वास्थ्य की सुविधाए उपलब्ध करायी जा सकती है। बैठक में परिवार नियोजन की सुविधाओ के बारे में डॉ0 स्मिता, टीकाकरण के बारे में डॉ0 जलज तथा आशा मानीटरिंग के बारे में आलोक राय ने विस्तार से जानकारी दिया। बैठक में सहायक शोध अधिकारी ने बताया कि सभी उपकेन्द्रों का प्रति सप्ताह के क्रियाकलापों का चार्ट तैयार है। इसी के अनुसार सभी उपकेन्द्र संचालित होंगे। बैठक में सीएमओ डॉ0 एके गुप्ता, नोडल अधिकारी डॉ0 सीके वर्मा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारीगण उपस्थित रहें।

चेयरमैन उनवल उमा शंकर निषाद ने कि मुख्यमंत्री से मुलाकात

गोरखपुर/खजनी तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर,उनवल के पहले अध्यक्ष के रूप में पिछड़ा बर्ग को महत्व दिया गया।जिसमें नगर के लोगो को विकास की अपार संभावनाएं बनती दिखी।लेकिन बीच का समय विकास पर भारी पड़ गया। इसमें अध्यक्ष की मांग को मुख्य मंत्री जी ने बड़ी चुनौती के रूप में लेते हुए निदान करने का भरोसा दिया है। उनके अतिप्रिय भक्तो में अध्यक्ष जी हमेशा रहे हैं। महत्व तो महाराज जी के लिए पूरा नगर पंचायत है। जिसको प्रदेश सरकार जानती है उसके कहे अनुसार विकास की रूप रेखा बनती बिगड़ती है।अध्यक्ष जी ने मुख्य मंत्री जी से मिल कर नगर की 15 सूत्री मांगों को रखा।इस मांग पत्र में प्रमुख और ज्वलंत मुद्दों को शामिल किया गया है।जिसका निदान नगर पंचायत फण्ड से नही हो पाता उसके लिए अतिरिक्त फण्ड की आवश्यकता पड़ती।

सूरजकुंड धाम में स्थित श्री रामजानकी मंदिर के पुजारी अवैध कब्जा करने वालों से और गंदगी से परेशान

गोरखपुर/श्री राम जानकी मंदिर जो सूरजकुंड धाम में स्थित है। मंदिर के पुजारी धर्मेन्द्र दास है और मंदिर की देखभाल का भी कार्य देखते है। यहाँ पर पिछले कई वर्षों से यज्ञ का आयोजन होता आ रहा है जो पुलिस प्रशासन की देख रेख में होता है। और कोर्ट से भी अनुमति ली जाती है। इस मंदिर के सामने वाली जमीन पर अवैध कब्जा करके कुछ लोग पशु बांधकर और नाद व गोबर रखकर काफी दुर्गंध पैदा करा रहें है।, जिससे मंदिर में रहकर पूजा पाठ करना दुर्लभ हो गया है। तथा साथ ही साथ गंभीर बीमारी के बढ़ने की संभावना बढ़ गई है जहां पिछले कई सालों से प्रवचन और भंडारा के लिए टेंट लगाया जाता है वहां अब गोबर और गंदगियों का फैलाव हो गया है। जिसे मना करने पर मारने-पीटने की धमकी देते हैं। और गाली-गलौज करते हैं शासन और प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद भी केवल और केवल आश्वासन ही मिलता है अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।

कृषि सुधार बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे सपा, कांग्रेस और भाकियू कार्यकर्ता

गोरखपुर/कृषि सुधार बिल के खिलाफ शुक्रवार को गोरखपुर-बस्ती मंडल के जिलों में कांग्रेस, सपा और भारतीय किसान यूनियन के कांग्रेसियों ने धरना-प्रदर्शन किया। सरकार से तत्काल इसे वापस लेने की मांग की। गोरखपुर में कांग्रेसियों ने नगर निगम में प्रदर्शन किया। कांग्रेसी बिल के विरोध में जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट की ओर निकले तो नगर निगम गेट पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस और कांग्रेसियों में नोकझोंक भी हुई लेकिन पुलिस ने कांग्रेसियों को नगर निगम से बाहर नहीं निकलने दिया। जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में कांग्रेसी नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में इकट्ठा हुए और सभा करने के बाद कलेक्ट्रेट जाने का निर्णय लिया। इसी तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को नए कृषि बिलों को वापस लिये जाने की मांग को लेकर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरना दिया।

चुनौती बन गये हैं बैंकों के फंसे कर्ज

इस वित्त वर्ष के शुरुआती तीन महीनों में अर्थव्यवस्था लगभग एक चौथाई सिकुड़ गयी. मुख्य वजह मार्च में शुरू किया गया सख्त लॉकडाउन रहा. एक महीने तक लगभग तीन चौथाई अर्थव्यवस्था ठप रही. इसके बाद मामूली छूट के साथ लॉकडाउन को जारी रखा गया. इस तिमाही में अर्थव्यवस्था को तिहरा झटका लगा- मांग, आपूर्ति और वित्तीय तंत्र ध्वस्त हो गया. अप्रैल में बेरोजगारी 30 प्रतिशत तक पहुंच गयी- करीब 12.2 करोड़ लोग रोजगार से हाथ धो बैठे. शहरों में औसतन 40 प्रतिशत कामगार प्रवासी हैं, उनके सामने आजीविका का संकट आ खड़ा हुआ. रोजगार और आमदनी छिनने से कई शहरी परिवारों के सामने खाने-पीने का संकट उत्पन्न हो गया. इससे राज्य सरकारों को आपात कदम उठाने पड़े. खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज की शुरुआत की और राशन को दोगुना करते हुए उसे नवंबर तक बढ़ा दिया. मई में केंद्र सरकार ने तरलता समर्थन के लिए 20 लाख करोड़ के बड़े पैकेज की घोषणा की. इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, तीन लाख करोड़ तक के ऋण के पात्र हैं. उक्त राशि में से लगभग आधी राशि स्वीकृति की गयी और ऋण वितरण किया जा रहा है. आश्चर्य नहीं कि ऋण के लिए मांग ठप है, क्योंकि पहले से ही छोटे उद्यम मांग की कमी से जूझ रहे हैं और वे कर्ज के अतिरिक्त बोझ को उठाने समर्थ नहीं हैं. लेकिन, जिन छोटे उद्यमों का नकदी प्रबंधन असंतुलित है यानी उनके पास लंबित बीजक (इनवायस) हैं, जो उनके ग्राहकों द्वारा भुगतान नहीं किये गये हैं, वे संकट से निपटने के लिए ऋण सहायता लेने के इच्छुक हैं. ऐसे छोटे बिजनेस अतरलता की समस्या से जूझ रहे हैं, न कि दिवालियापन से. अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में लगभग यही हालात हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग आठ लाख करोड़ रुपये की तरलता जारी की है. इसमें ब्याज दरों में कटौती, बैंकों से सरकारी बॉन्ड की खरीद (ओपेन मार्केट ऑपरेशन) और विदेशी मुद्रा खरीद तथा नकदी जारी करना आदि शामिल है. आरबीआइ ने वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों को कम-लागत लंबी-

अवधि के फंड दिये हैं. इसे दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन कहा जाता है. इसमें ज्यादातर तरलता बढ़ाते हैं. नकदी उपलब्धता, ऋण वृद्धि नहीं कर पायी, इसके बजाय शायद शेयर बाजार में चली गयी. विदेशी धन का अंतर्वाह और भारतीय बैंकिंग में अत्यधिक तरलता ही मुख्य कारण हैं कि मार्च में बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक मार्केट अब 50 प्रतिशत से अधिक उबर गया है. तिहरे झटकों में से एक प्रकार के झटके से हम उबर चुके हैं यानी कि वित्तीय झटका. जब जीडीपी सिकुड़ चुकी है और आपूर्ति व मांग की चुनौतियां बरकरार हैं, दूसरी तिमाही में जीडीपी में कुछ सुधार के संकेत दिख सकते हैं. लेकिन, विकास दर अभी भी नकारात्मक बनी रहेगी. सर्वेक्षण के मुताबिक, आधे से अधिक परिवारों की आय बीते वर्ष की तुलना में कम ही रहेगी. व्यवसाय भी कोविड-पूर्व राजस्व पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. ऐसी दशा में, उद्योगों के लिए बैंक ऋण अधिक तनावपूर्ण होगा. जुलाई में जारी आरबीआइ की छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में, पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च, 2020 से मार्च 2021 के बीच चार प्रतिशत बिंदु की दर से बढ़ सकता है. यह बैंक ऋण के चार लाख करोड़ को बट्टे-खाते में डालने के कारण है. अगर हालात अत्यधिक गंभीर थे, तो एनपीए अनुपात दो प्रतिशत अधिक, 14.7 प्रतिशत तक हो सकता है. इसका मतलब हुआ कि अतिरिक्त दो लाख करोड़ बट्टे-खाते में जायेंगे. बैंकों का जोखिम समायोजित पूंजी अनुपात इन बट्टे-खातों के लिए पर्याप्त है. आरबीआइ द्वारा दरों में कटौती के बावजूद बैंक अच्छे कर्जदारों को कम ब्याज लागत देने में असमर्थ हैं, क्योंकि एनपीए का बोझ बढ़ रहा है. बैंकों की इस समस्या के साथ-साथ ऋण अधिस्थगन (लोन मोरेटोरियम) भी है. महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए आरबीआइ ने मार्च से शुरू हुए ऋणों पर तीन महीने की मोरेटोरियम की घोषणा की थी. इसे और तीन महीनों के लिए अगस्त के अंत तक बढ़ाया गया. अभी मोरेटोरियम का मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और अगली सुनवाई की तारीख 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. कर्जदार ब्याज में छूट के साथ भुगतान देरी के कारण लगनेवाले ब्याज पर ब्याज में भी राहत चाहते हैं. यह बैंक जमाकर्ताओं और शेयरधारकों पर अनुचित बोझ प्रतीत होता है. वास्तव में अगर उधारकर्ताओं को राहत मिलनी चाहिए, तो वह राजकोषीय राहत हो, जो कि केंद्र सरकार की निधि से हो. लेकिन, इस प्रकार मोरेटोरियम चुननेवाले उधारकर्ताओं को आंशिक छूट और जो नहीं चुने हैं उन्हें छूट न मिलना, भी समस्यात्मक है. बड़ा सवाल है कि महामारी के हालात में बैंकों के स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाना चाहिए. आरबीआइ द्वारा बनायी गयी केवी कामथ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 26 सेक्टरों को चिह्नित किया गया है, जिनके लिए ऋणों का पुनर्गठन करना होगा, ताकि उन्हें एनपीए के रूप में न गिना जाये. कमेटी ने सावधानीपूर्वक क्षेत्रों को चिह्नित किया है, जो सीधे तौर पर महामारी से प्रभावित हुए हैं और उन्हें राहत की जरूरत है. लेकिन, जो महामारी के पहले से ही खराब दशा में थे, उनसे अलग तरह से निपटने की जरूरत है. बैंकिंग सेक्टर के ऋण का करीब 72 प्रतिशत कोविड की वजह से प्रभावित हुआ है और उसे कुछ हद तक पुनर्गठन की आवश्यकता है. अनुशंसाएं स्पष्ट मानकों पर आधारित हैं और बैंकों को हल्के, मध्यम और गंभीर रूप से संकट की श्रेणी में विभाजित किया गया है. अगस्त के आंकड़े दर्शाते हैं कि औद्योगिक ऋण मांग में बढ़त नहीं है. केयर रेटिंग रिपोर्ट के मुताबिक, पहली तिमाही के दौरान 19 प्रमुख औद्योगिक समूहों में से 13 की ग्रोथ निगेटिव रही. अन्य छह की ग्रोथ पॉजिटिव या शून्य रही. लाभदायक नहीं सही, तो व्यवहार्य बने रहने के लिए बैंकों के ऋण मांग में स्वस्थ वृद्धि की आवश्यकता है. फंसे कर्जों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंकों को केंद्र सरकार के खजाने से बड़ी इक्विटी की दरकार है. इस वित्तीय चुनौती से बचने के लिए कोई राह आसान नहीं है।

सम्पादकीय

नदियों को बांधने की कीमत

बिहार की बागमती नदी से बाढ़-सुरक्षा दिलाने की बात एक बार फिर चर्चा में है। यह नदी काठमांडू से करीब 16 किलोमीटर उत्तर-पूर्व शिवपुरी पर्वतमाला से निकलकर 195 किलोमीटर की यात्रा करती हुई सीतामढ़ी जिले के ढेंग नामक स्थान में भारत में दाखिल होती है। यहां से यह 394 किलोमीटर की यात्रा करती हुई बद्लाघाट (खगड़िया) में कोसी में मिल जाती है। अपनी उपजाऊ सिल्ट (गाद) और सदानीरा स्वरूप के कारण यह नदी पवित्र मानी जाती है। हालांकि, उत्तर बिहार की अन्य नदियों की तरह अपनी धारा बदलने के लिए यह भी कुख्यात है। सन 1750 से 1983 तक इसकी धारा में 11 बार परिवर्तन के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। धारा-परिवर्तन का सीधा संबंध बाढ़ से है और बाढ़ नदी क्षेत्र में बसने वाले लोगों की जीवनचर्या का अभिन्न अंग है। गाद से होने वाले लाभ और पानी की प्रचुरता ने हमारे पूर्वजों को बाढ़ क्षेत्र में बसने के लिए प्रेरित किया होगा। यह सौदा हमेशा फायदेमंद रहा है। बहरहाल, आजादी के काफी पहले से कोसी नदी की बाढ़ चर्चा में थी और उस समय बाढ़ से बचने का एक ही सहज उपाय था, तटबंधों का निर्माण। बांध बन जाने से नदी की पेटी का ऊपर उठना, सुरक्षित क्षेत्र में जल-जमाव, तटबंधों को ऊंचा करते रहने की मजबूरी और उनका टूटना सामान्य घटनाएं हैं। अंगरेज सरकार ने कोसी को नियंत्रित करने के लिए मनसूबे बांधे, मगर किया कुछ नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी आमदनी के लिहाज से यह घाटे का सौदा है। दामोदर नदी को बांधकर धोखा खाने के बाद उसने 1860 के दशक में ही बांधों से तौबा कर ली थी। देश आजाद हो जाने के बाद हमारी सरकार ने कुछ अलग करने की नीयत से नदियों के किनारे तटबंध बनाने शुरू किए और जाहिर था, यह काम कोसी से शुरू किया जाता। सन 1955 से कोसी पर तटबंधों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। बिहार में कोसी के तटबंधों का काम जब शुरू हुआ, तभी यह लगभग तय हो गया था कि गंडक परियोजना में भी हाथ लग जाएगा। इन दोनों ही नदियों के साथ-साथ अन्य नदियों के इलाके की जनता और उनके नेताओं में भी कुछ कर गुजरने का भाव जगा। कोसी व गंडक को लेकर तो पहले से भी कुछ तैयारी थी, मगर बागमती या कमला, बूढ़ी गंडक जैसी नदियों के हिस्से में सिर्फ बातें थीं। इन क्षेत्रों के लोगों ने अपने-अपने नेताओं पर दबाव डाला और वे मुखर भी हुए। नतीजतन, इन नदियों से बाढ़-सुरक्षा की भी बात चली। लेकिन उस वक्त तक इंजीनियरों का मत था कि धारा बदलने वाली अस्थिर नदी पर तटबंध बनाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे परेशानियां बढ़ जाती हैं। यह बात अलग है कि कोसी जैसी अस्थिर नदी पर भी बांध बनाए ही जा रहे थे। अब वे परेशानियां क्या-क्या हैं, उन्हें हम सभी भोग चुके हैं। बागमती एक अस्थिर नदी है, पर उसकी काट खोज ली गई कि यह नदी निचले छोर पर स्थिर है और हायाघाट से लेकर इसके कोसी से संगम तक तटबंध बनाए जा सकते हैं, और वे1950 के दशक में बन भी गए। लेकिन उसके साथ यह भी कहा गया कि हायाघाट के प्रति-प्रवाह में बागमती स्थिर नहीं है, इसलिए हायाघाट और ढेंग के बीच तटबंध नहीं बनाए जाने चाहिए। लेकिन इस अस्थिर भाग में भी ढेंग से सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर तक 1970 के दशक में तटबंध बना दिया गया। तब तर्क यह दिया गया था कि नदी का बीच का भाग, जो रुन्नी सैदपुर से लेकर हायाघाट तक का क्षेत्र है, एक तश्तरी जैसा है और उसी इलाके में नदी अस्थिर है। इसलिए उसको खुला छोड़ देना चाहिए, ऊपर वाले क्षेत्र में बांध बनाना चाहिए। और वह स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद 1975 तक आते-आते तैयार भी कर दिया गया। वर्ष 2007 की राज्यव्यापी बाढ़ ने बागमती के बीच वाले हिस्से पर तटबंध बनाने की चाहत को नए सिरे से हवा दी। अब इस इलाके की, जहां नदी तकनीकी तौर पर अस्थिर मानी जाती थी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है और स्थानीय लोगों की इच्छा के विरुद्ध यह कोशिश हो रही है कि इस हिस्से में भी नदी को घेर लिया जाए। स्थानीय जनता इन तटबंधों के खिलाफ है। अव्वल तो यह क्षेत्र एक तश्तरी की तरह है, फिर तटबंध की ऊंचाई यहां ज्यादा होगी, क्योंकि जमीन नीची है। यह बांध पानी की निकासी में बाधा डालेगा और बरसात में जो पानी यहां जमा होगा, वह नदी में जाएगा ही नहीं। नतीजतन, इस तश्तरी में अटका पानी या तो हवा में भाप बनकर उड़ेगा या धरती में रिस-रिसकर समाप्त होगा। इसका खेती पर भी बुरा असर पड़ेगा। फिर तटबंध टूटेगा नहीं, इसकी गारंटी कौन लेगा? सरकारी रिकॉर्डों के हिसाब से ही बागमती नदी के तटबंध 1987 से 2010 के बीच 58 बार टूटे हैं। इतना ही नहीं, जो तटबंध अब बनने जा रहा है, उसके बीच में मुजफ्फरपुर जिले के कटरा व गायघाट प्रखंड, समस्तीपुर जिले का कल्याणपुर प्रखंड और दरभंगा जिले के सिंघवारा, हनुमाननगर, बहादुरपुर व हायाघाट प्रखंडों के 109 गांव आएंगे। उनका क्या हश्र होगा, यह किसी से छिपा नहीं है, खासतौर से यह देखते हुए कि हायाघाट से बद्लाघाट तक बांध-निर्माण की वजह से विस्थापित लोगों के पुनर्वास का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ढेंग से रुन्नी सैदपुर तक जो 94 गांव तटबंधों के बीच फंसे थे, उन सबका पुनर्वास भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। आम जनता को बाढ़ से सुरक्षा चाहिए, लेकिन वह मिल सकेगी और उसके लिए क्या कीमत चुकानी होगी, इस पर विचार जरूरी है। नदियों को स्थिर होने में सदियां गुजर जाती हैं। फिर, हम उन बूढ़े-बुजुर्गों को क्या कहेंगे, जो कहते नहीं थकते कि पहले पानी आता था और चला जाता था।

खेती के कारपोरेटीकरण का विधेयक

सरकार ने विपक्ष के भारी विरोध के बाद भी खेती से सम्बंधित विधेयक पास कर दिया। लोकसभा में तो सरकार के पास अपनी ही पार्टी के सदस्यों का स्पष्ट बहुमत था, वहां पास होना ही था। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के कई नेताओं ने मतविभाजन के बाद बिल को रोकना चाहा, लेकिन उपाध्यक्ष ने ध्वनिमत से पास करवा कर लोकसभा में पास हुए दोनों विधेयकों को राज्यसभा की हरी झंडी दे दी और राष्ट्रपति भवन का रास्ता दिखा दिया। ऐसा लगता है कि ध्वनिमत का सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रही पार्टियों ने भी इन विधेयकों का विरोध किया है। इस कानून के बन जाने के बाद खेती किसानी वही नहीं रहेगी जो अब तक रहती रही है। हमेशा से ही इस देश का किसान खेती की उपज के जरिये सम्पन्नता के सपने देखता रहा है। हर स्तर से मांग होती रही है कि खेती में सरकारी निवेश बढ़ाया जाय, भण्डारण और विपणन की सुविधाओं के ढांचागत निवेश का बंदोबस्त किया जाय जिससे कि किसान को अपने उत्पादन को कुछ दिन तक मंडी में भेजने से रोकने की ताकत आये जिससे वह अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर न हो। एक बात बिल्कुल अजीब लगती है कि शहरी मध्यवर्ग के लिए हर चीज महंगी मिल रही है जिसको किसान ने पैदा किया है। उस चीज को पैदा करने वाले किसान को उसकी वाजिब कीमत नहीं मिल रही है। किसान से जो कुछ भी सरकार खरीद रही है उसका लागत मूल्य भी नहीं दे रही है। किसान को उसकी लागत नहीं मिल रही है और शहर का उपभोक्ता कई गुना ज्यादा कीमत दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बिचौलिया मजा ले रहा है। किसान और शहरी मध्यवर्ग की मेहनत का एक बड़ा हिस्सा वह हड़प रहा है। और यह बिचौलिया गल्लामंडी में बैठा कोई आढ़ती नहीं है। वह आवश्यक वस्तुओं के क्षेत्र में सक्रिय कोई पूंजीपति भी हो सकता है और किसी भी बड़े नेता का व्यापारिक पार्टनर भी। इस हालत को संभालने का एक ही तरीका है कि जनता अपनी लड़ाई खुद ही लड़े। उसके लिए उसे मैदान लेना पड़ेगा और सरकार की पूंजीपतिपरस्त नीतियों का हर मोड़ पर विरोध करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आज की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है। उसकी सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल आवाजें तो तरह-तरह की निकाल रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्होंने किसानों के बारे में पारित विधेयकों को एहसान फ़रामोशी के बिल कहा है। आम तौर पर बीजेपी को संसद में समर्थन देने वाली पार्टियों बीजू जनता दल और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी इन विधेयकों का विरोध किया है। खेती में सरकारी निवेश की बात हमेशा से होती रही है। 1965 के बाद जो हरित क्रान्ति आई थी, वह भी बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश का नतीजा थी। सरकार ने रासायनिक खाद, सिंचाई के साधन, बीज जैसी जरूरी चीजों को सब्सिडी के रास्ते सस्ता कर दिया था। सरकारी खरीद की व्यवस्था की गई थी। न्यूनतम मूल्य की गारंटी की गई थी यानी आढ़ती या किसी जखीरेबाज की मर्जी से अपनी फसल बेचने के लिए किसान मजबूर नहीं था। अपने उत्पादन का कंट्रोल उसके पास ही था। पिछले चालीस साल से सरकार से उसी तरह की एक क्रान्ति की बात की जाती रही है। उम्मीद की जा रही थी कि कृषि उपज के भंडारण और विपणन में बड़े पैमाने पर सरकारी पूंजी का निवेश कर दिया जाए, अमूल जैसी कंपनियों की व्यवस्था कर दी जाए और किसान को अधिक उत्पादन के अवसर उपलब्ध कराये जाएं। अगर ऐसा हुआ होता तो किसान की सम्पन्नता बढ़ती और देश में तेजी से बढ़ रहे मध्यवर्ग के परिवारों में किसान भी बड़ी संख्या में शामिल होते। लेकिन सरकार ने पूंजी निवेश नहीं किया। उससे पलट कारपोरेट क्षेत्र को खेती किसानों के उत्पादन पर नियंत्रण की खुली छूट दे दी। सरकारी मंडियां ख़त्म कर दी गईं, किसान को निजी पूंजी के मालिकों के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया। मुख्य विपक्षी पार्टी, कांग्रेस जब सरकार में थी तो वह भी यही करना चाहती थी। इसलिए इस बिल का विरोध असली मुद्दों पर नहीं किया जा रहा था। सारा फोकस न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर केन्द्रित कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि एमएसपी तो रहेगा। लेकिन सरकार अब कोई खरीद नहीं करेगी। यानी जो कारपोरेट खेती की उपज खरीदेगा उसके लिए दिशानिर्देश के तौर पर एमएसपी घोषित कर दिया जाएगा लेकिन खरीद वह अपनी मर्जी से करेगा। सैद्धांतिक रूप से उसकी खरीद की कीमत एमएसपी से ज्यादा भी हो सकती है लेकिन अगर सरकारी खरीद का ढांचा खत्म हो गया तो उसको मनमानी करने से कौन रोक पायेगा।

पहले भी जब सरकारी अफसर, मंत्री, सत्ताधारी पार्टियों के नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते थे तो लगता था कि वे किसानों को कुछ खैरात में दे रहे हैं। कई बार तो ऐसे लगता है जैसे किसी अनाथ को या भिखारी को कुछ देने की बात की जा रही हो। यह किसान का अपमान है और उसकी गरीबी का मजाक है। वह अपने को दाता समझते थे और किसान को प्रजा। राजनीतिक नेता और मंत्री जनता के वोट की मदद से सत्ता पाते हैं। अजीब बात है कि जिस देश में सत्तर प्रतिशत आबादी किसानों की है वहां यह सत्ताधीश सबसे ज्यादा उसी किसान को बेचारा बना देते हैं। किसानों के हित के लिए सरकार में जो भी योजनाएं बनते हैं वे किसानों को अनाज और खाद्य पदार्थों के उत्पादक के रूप में मानकर चलती हैं। नेता लोग किसान को सम्पन्न नहीं बनने देना चाहते। इस मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि लागत का मूल्य नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि किसान के लिए बनी हुई संस्थाएं उसको प्रजा समझती हैं। न्यूनतम मूल्य देने के लिए बने संगठन, कृषि लागत और मूल्य आयोग का तरीका वैज्ञानिक नहीं है। वह पुराने लागत के आंकड़ों की मदद से आज की फसल की कीमत तय करते हैं जिसकी वजह से किसान ठगा रह जाता है। फसल बीमा भी बीमा कंपनियों के लाभ के लिए डिजाइन किया गया है। खेती की लागत की चीजों की कीमत लगातार बढ़ रही है लेकिन किसान की बात को कोई भी सही तरीके से नहीं सोच रहा है जिसके कारण इस देश में किसान तबाह होता जा रहा है। किसानों को जो सरकारी समर्थन मूल्य मिलता है वह भी लागत मूल्य से कम होता है। सरकारी खरीद होती नहीं और निजी हाथों में फसल बेचने पर जो दाम मिलता है बहुत कम होता है। अब सरकार ने कानून तो पास करवा लिया है लेकिन उस पर दबाव पूरा है। 25 सितम्बर को कुछ राज्यों में किसानों ने बंद का आह्वान किया है। देशव्यापी आन्दोलन भी चल रहा है। किसानों पर सरकार ने एक और फैसला आनन फानन में कर लिया है। संसद के सत्र के आखिरी दिन आई कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की एक रिपोर्ट में आयोग ने सीधे किसानों को सब्सिडी देने की सिफारिश करते हुए सालाना 5 हजार रुपये देने की सिफारिश कर दी है आयोग के मुताबिक, किसानों को 2,500 रुपये की दो किस्तों में भुगतान किया जाए। पहली किस्त खरीफ की फसल शुरू होने से पहले और दूसरा भुगतान रबी की शुरुआत में किया जाए, ताकि किसानों को बुआई में धन की कमी न हो। अगर सरकार इन सिफारिशों को मंजूर करती है, तो अभी कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। किसान अभी यूरिया, पोटाश और फॉस्फेट को बाजार खाद कंपनियों को दी गई सब्सिडी पर खरीदते हैं। इन कंपनियों को खाद की बिक्री के बाद सरकार सब्सिडी का भुगतान करती है। नई प्रक्रिया के तहत किसानों को उर्वरक बाजार मूल्य पर मिलेंगे और सब्सिडी सीधे उनके खाते में आएगी और किसान को कंपनी की तरफ से तय किये गए दाम पर खाद खरीदनी पड़ेगीयहां भी खाद कंपनी को मनमानी की छूट दे दी गई है।अब सरकार ने खेती से सम्बंधित सारी पहल निजी हाथों में सौंप दिया है। ठेके पर खेती की बात भी की जा रही है। नए कानून में यह व्यवस्था है कि कोई भी कंपनी किसान से बुवाई के पहले ही उसकी उपज का दाम तय करके उससे समझौता कर लेगी। सरकार इस को बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही है। जबकि इसकी सच्चाई यह है कि किसान को अपनी उपज की कीमत पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। जिस दाम पर भी समझौता हुआ है, उससे ज्यादा दाम अगर कहीं मिल रहा है तो वह नहीं बेच सकेगा। इस देश की कारपोरेट संस्कृति ऐसी है कि किसान को खूब दबाकर दाम तय कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर नए कानून के बाद जो स्थितियां बनेगीं उसमें किसान की पैदावार की लगाम उसके हाथ में नहीं, कारपोरेट कंपनी के हाथ में होगी। और अगर ठेके की खेती करने वाली कोई कंपनी आ जायेगी तो किसान को उसकी जमीन का किराया ही हाथ आयेगा, उपज से उसका कोई नहीं रहेगा। इस कानून ने खेती किसानी को कारपोरेट हाथों में सौंप दिया है।

बरसते पानी में डूबता किसान

विभिन्न कृषि विशेषज्ञों की मानें तो किसानों की समस्याओं को केवल योजनाएं बना देने से नहीं निपटाया जा सकता, योजनाओं को प्रभावशाली तरीके से लागू भी करना पड़ेगा, और साथ ही कपास के हाइब्रिड बी.टी. बीजों से किनारा करना पड़ेगा, क्योंकि इन हाइब्रिड बीजों में ज्यादा बीमारियां आती हैं और उनका कोई इलाज भी नहीं होता, इसलिए क्षेत्र और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर नए देसी बीज तैयार करने पड़ेंगे। ल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने इस वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी के जो आंकड़े जारी किए, उनसे आसानी से समझा जा सकता है कि भारत में आर्थिक मंदी ने अपने पैर पसार लिए हैं और 23.9 प्रतिशत के ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। वहीं संतोष की बात यह है कि कृषि क्षेत्र जिसका जीडीपी में लगभग 16 फीसदी हिस्सा है, और 50 फीसदी कामगारों को अपने में समाए हुए है, में 3.9 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस बार रिकार्ड अनाज पैदा किया है। इससे किसानों में थोड़ा हौसला आया था परन्तु अब चिन्ता इस बात की है कि खरीफकी फसलों में हो रहे भारी नुकसान से सरकारें और किसान कैसे निपटेंगे? कृषि प्रधान राज्यों हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में खरीफ के मौसम में मुख्यतरू कपास और चावल की खेती की जाती है, परन्तु इस बार कपास के किसानों को चौतरफा मार झेलना पड़ रहा है, सबसे पहले कोरोना की वजह से कपास के बीज में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए और बीज महंगे मिले और नकली होने का भी डर लगातार बना रहा।उसके बाद जून के अंत में और जुलाई के शुरू में टिड्डियों के आक्रमण से पूरे के पूरे खेत बर्बाद हुए। उसके बाद जो बचे रह गए उनमें अब अगस्त के अंत में सफेद मक्खियों के आक्रमण ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है, और औसत से ज्यादा बारिश ने आग में घी डालने का काम किया। ज्यादा बारिश से भी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हाल ही में हरियाणा की बात करें तो लगभग 75 प्रतिशत कपास की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं , जिनमें से अधिकतर किसानों ने जमीन किराए पर लेकर फसल बोई थी, क्योंकि कोरोना की वजह से बड़े शहरों से लौटे लोगों के पास खेती करने के अलावा और कोई काम नहीं था, इसलिए इस बार पिछले साल के मुकाबले जमीन का किराया भी दो से तीन हजार रुपए प्रति एकड़ बढ़ गया। हम हरियाणा के भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद और पंजाब के मानसा, फाजिल्का, और बठिंडा के 31 किसानों से बात करने के बाद इस विश्लेषण पर पहुंचे हैं कि लगभग 25 से 27 हजार रुपए प्रति एकड़ जमीन किराए पर ली और अब तक उसमें 17 से 19 हजार रुपए प्रति एकड़ खर्चा हो चुका है जिसमें खुद की शारीरिक मेहनत को नहीं जोड़ा गया, और अब उनकी फसलें लगभग 75 से 80 फीसदी खराब हो चुकी है, कुछ किसानों की तो पूरी की पूरी फसलें खराब हो चुकी है जैसे सिरसा जिले के डबवाली क्षेत्र में पूरी फसलें खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान है और किसानों में सरकारों के खिलाफ भी रोष है। ऐसे कृषि संकटों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसे वर्ष 2016 में लागू किया गया था, कारगर साबित हो सकती है, परन्तु ये योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई। जब इसे लागू किया गया तब खरीफ की प्रीमियम दर 2 प्रतिशत और रबी के लिए 1.5 प्रतिशत थी, और शुरू के वर्षों में इसे उन किसानों के लिए जरूरी किया गया जिन्होंने बैंक से किसी न किसी प्रकार का कृषि लोन ले रखा है। उनके बैंक खातों से अपने आप बिना उनसे पूछे कटौती की गई, और किसानों को 6 महीने बाद जब बैंक की किस्त चुकाने गए तब पता चला कि उनकी फसल का बीमा हो रखा था। दूसरा किसानों को ये भी नहीं पता कि फसल खराब होने पर कहां जाना है, कौन कम्पनी है जो बीमा राशि का भुगतान करेगी, क्या शर्तें है, नुकसान मापने के क्या पैमाने है, कौन नापेगा, सब कुछ अपारदर्शी था, फिर किसानों और उनसे जुड़े संगठनों ने आवाज उठाई, उसके बाद किसानों को विकल्प दिया गया कि जिन्हें बीमा नहीं करवाना वो अपने बैंक में जाकर एक फार्म भर दें, तो जिन किसानों ने पिछले 5-6 फसलों से बीमा का प्रीमियम भरा था उन्होंने उसे बंद करवा दिया, क्योंकि पैसे जा रहे थे पर फायदा नहीं मिल रहा था, फसलें हर साल कुछ हद तक खराब होती है, परन्तु बीमा राशि तब तक नहीं मिलती जब तक कि पूरे गांव की 75 प्रतिशत फसल खराब ना हो जाए, और नुकसान मापने के लिए गिरदावरी का काम पटवारी या उनके कोई सहयोगी करते हैं, और ये लोग कम्पनी से मिल कर किसानों का नुकसान को बहुत कम दर्शाते हैं। इससे संबधित कई बार शिकायतें देखने को मिली है कि पटवारी ने लिख दिया कि इस किसान की 30 प्रतिशत फसल खराब हुई है जबकि उसकी सारी की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी, ऐसे और भी अनेक मामले सामने आए है जहां किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। हरियाणा के सिरसा व फतेहाबाद जिले के किसानों का कहना है कि उनको केवल जनवरी फरवरी 2019 में, लोकसभा चुनावों से पहले एक बार बीमा राशि प्राप्त हुई है और वो किस आधार पर हुई है, क्यों हुई है किसी को मालूम नहीं, और जिन लोगों ने जमीन किराए पर ली हुई थी उन लोगों को तो आज तक कभी प्राप्त ही नहीं हुई। क्योंकि बीमा जमीन के मालिक के नाम से हुआ था। ऐसे अनेक कारणों की वजह से किसान इस योजना से दूर भाग रहे हैं। हालांकि सरकार ने जनवरी 2020 में इस योजना में कुछ बदलाव किए हैं और राज्यों व कम्पनियों को सख्ती से इस योजना को लागू करने की बात कही है, बावजूद इसके 2016 के मुकाबले इस बार किसानों ने बहुत कम संख्या में फसल बीमा करवाया है। इसकी एक वजह ये है कि बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य पिछले खरीफ मौसम से इस स्कीम से अपने आप को अलग किए हुए हैं वहीं गुजरात ने भी मार्च 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत कर दी है। वहीं पंजाब जो कि कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है ने कभी इस योजना को लागू ही नहीं किया था। अब प्रश्न ये बनता है कि इन राज्यों में केवल पश्चिम बंगाल को छोड़ कर बीजेपी या बीजेपी के समर्थन प्राप्त दल की सरकारें है, (2016 में जब इस योजना को शुरू किया गयातब पंजाब में अकाली भाजपा की सरकार थी) बावजूद इसके ये राज्य इस योजना को लागू नहीं कर रहे, क्यों?ऐसे ही कुछ शंकाओं के चलते लगभग 50 से 55 फीसदी किसानों ने इस बार इस योजना के तहत बीमा नहीं करवाया हुआ, परन्तु अब जब सारे किसानों की कपास की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है तब इन किसानों के पास क्या विकल्प रह जाता है? अब किसानों ने सरकारों की तरफ झांकना शुरू कर दिया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल ने घोषणा भी की है कि जल्दी ही गिरदावरी करके किसानों को मुआवजा प्रदान किया जायेगा, अब ये कब तक हो पायेगा इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है।परन्तु फिर भी एक बार ये प्रश्न खड़ा हो गया है कि डूबते किसान को कैसे बचाया जाए, क्योंकि डूबती अर्थव्यवस्था में केवल कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो हमारी अर्थव्यवस्था को इस मंदी और संकट के दौर से बाहर निकाल पाने में सबसे अहम योगदान दे सकता है।विभिन्न कृषि विशेषज्ञों की मानें तो किसानों की समस्याओं को केवल योजनाएं बना देने से नहीं निपटाया जा सकता, योजनाओं को प्रभावशाली तरीके से लागू भी करना पड़ेगा, और साथ ही कपास के हाइब्रिड बी.टी. बीजों से किनारा करना पड़ेगा।

सार समाचार .....

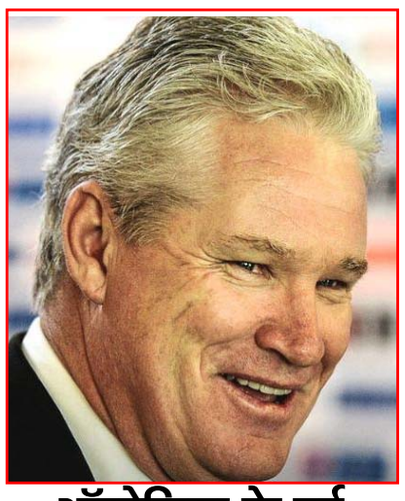

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोन्स का हार्ट अटैक से निधन

नई दिल्ली **एजेंसी।**

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व मिडल ऑर्डर बल्लेबाज और क्रिकेट एक्सपर्ट डीन जोन्स का मुंबई के एक होटल में गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। 59 साल के जोन्स इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के क्रिकेट कमेंट्री पैनल में थे। सेवन स्टार होटल में उन्हें बायो सिक्योर बबल के तहत ठहराया गया था। जोन्स का जन्म मेलबर्न में हुआ था। उन्होंने 52 टेस्ट में 3631 रन बनाए। इस दौरान उनका एवरेज 46.55 रहा। 216 का बेस्ट स्कोर रहा। उन्होंने 11 शतक लगाए। एलन बॉर्डर की कप्तानी में उन्होंने ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट खेला।

चेन्नई टेस्ट में 210 रन की पारी खेली थी

जोन्स ने 164 वनडे मैच में 6063 रन बनाए हैं। इसमें 7 सेंचुरी और 46 हाफ सेंचुरी भी शामिल है। उन्हें 1986-87 में भारतीय दौरे के बाद काफी प्रसिद्धि मिली थी। भारत के साथ चेन्नई (मद्रास) में पहले टेस्ट मैच में वह गर्मी के कारण थक गए थे। उन्हें चक्कर आ गया था। जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। लेकिन वे हार नहीं मानें और हॉस्पिटल से आने के बाद उन्होंने मैच खेला था। इस मैच में उन्होंने 210 रन बनाए थे। यह टेस्ट टाई रहा था।

टी-20 इंटरनेशनल में विराट से भी आगे निकलने वाली महिला क्रिकेटर ने कही ये अहम बात

डर्बी एजेंसी। वेस्टइंडीज की महिला खिलाड़ी स्टाफानी टेलर टी-20 इंटरनेशनल में 3,000 रनों का आंकड़ा छू कर काफी खुश हैं. वो महिला एवं पुरुष क्रिकेट दोनों में यह मुकाम हासिल करने वाली दूसरी और वेस्टइंडीज की पहली क्रिकेटर हैं. टेलर ने यह मुकाम बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी-20 मैच में हासिल किया था. उनकी टीम हालांकि यह मैच 47 रनों से हार गई. टेलर ने 105 टी-30 मैचों में कुल 3,020 रन बनाए हैं. उनसे आगे न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स हैं जिन्होंने 119 मैचों में 3,243 रन बनाए हैं. क्रिकेट टेलर ने कहा, मैं आंकड़ों पर विश्वास करने वाली खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन जब यह बड़ी स्क्रीन पर आया तो यह शानदार एहसास था. ये बताता है कि हम महिला क्रिकेटरों ने इतने सालों में कितनी मेहनत की है और लोगों का इसे इतना सम्मान देने को देखकर मैं अभिभूत हूं महिला क्रिकेट में बेशक लोगों को ध्यान न जाता हो लेकिन टेलर के टी-20 अंतर्राष्ट्रीय में भारत के विराट कोहली और वेस्टइंडीज के क्रिस गेल से भी ज्यादा रन हैं. विराट के नाम 2,794 रन हैं तो गेल ने 1,627 रन बनाए हैं. टी-20 में वह 100 विकेट लेने से 7 विकेट दूर हैं।

इस मैच पर सट्टा लगाने वालों पर शिकंजा

कोलकाता एजेंसी। कोलकाता के विभिन्न हिस्सों से इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के मैच पर सट्टा लगाने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि पुख्ता जानकारी के आधार पर कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग के अधिकारियों ने हारे स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट, जादवपुर और सॉल्ट लेक इलाके में गुरुवार रात छापे मारे और 9 लोगों को गिरफ्तार किया. इन पर एक दिन पहले हुए आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने का आरोप है. ये मैच किंग्स इलेवन पंजाब और आरसीबी के बीच खेला जा रहा था. उन्होंने बताया कि इनके पास से कई दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट और एक वाहन जब्त किया गया है. अधिकारी ने कहा, 'मामले की जांच की जा रही है और हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी अंतरराज्यीय सट्टा गिरोह से तो नहीं जुड़े हैं.' कुछ दिनों पहले हरियाणा में ऐसा ही एक मामला सामने आया था. गुरुग्राम पुलिस ने 23 सितंबर को कहा था कि उसने राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच पर सट्टा लगाने वाले 2 युवक गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, सट्टा लगाने वालों को गुरुग्राम के सेक्टर 107 से गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 1 सूटकेस, 8 मोबाइल फोन, 1 नोटबुक, 1 लैपटॉप और 1 पेन ड्राइव जब्त की गई है. गिरफ्तार किए गए आरोपी दिल्ली के नांगलोई इलाके के रहने वाले वीरेंद्र (27) और राकेश कौशिक (35) हैं।

बल्लेबाजी क्रम में सुधार चाहेंगी चेन्नई, दिल्ली

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा। चेन्नई ने मुंबई को हराकर जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम को हरा दिया था।

दुबई एजेंसी।

राजस्थान के खिलाफ टीम के गेंदबाजों ने काफी रन लुटाए थे और चेन्नई को जीत के लिए 217 रनों की चुनौती दी थी। चेन्नई काफी कोशिश की बाद 16 रनों से मैच हार गई थी। गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में भी टीम ने कुछ खास नहीं किया था। सिर्फ फाफ डु प्लेसिस का बल्ला चला था बाकी सभी असफल रहे थे। पहले मैच में फाफ के साथ टीम को जीत दिलाने वाले बल्लेबाज अंबाती रायडू दूसरे मैच में नहीं खेले थे। उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड को उतारा गया था जो पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। रायडू के दूसरे मैच में खेलने पर अभी भी अनिश्चित्ता है और यह चेन्नई के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है। पिछले दो मैचों में चेन्नई की सलामी जोड़ी असफल रही है। न मुरली विजय चले हैं और न ही शेन वाटसन। दूसरे मैच में टीम को बड़े स्कोर के सामने जिस तरह की शुरूआत चाहिए थी वो यह दोनों दे नहीं पाए थे। चेन्नई की समस्या मध्य क्रम की भी है। केदार जाधव, ऋतुराज खुद, धोनी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। धोनी ने पिछले दोनों मैचों में इंग्लैंड के युवा सैम कुरैन को अपने से ऊपर भेजा था। चेन्नई के लिए धोनी का स्थान एक चर्चा का विषय है। धोनी ने पिछले मैच में नंबर-7 पर बल्लेबाजी की थी, लेकिन जब तक वो आए थे और जिस तरह से शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे उससे कई सावल खड़े हुए थे। उन्होंने आखिरी ओवर में तीन छक्के जरूर लगाए थे, लेकिन टीम के लिए उनका मतलब नहीं रह गया था। अब देखना होगा कि रायडू की अनुपस्थिति में धोनी ऊपर आकर टीम को संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं या फिर नीचे ही खेलते हैं। वहीं गेंदबाजी की बात की जाए तो पिछले मैच में चेन्नई के स्पिनरों ने खूब रना लुटाए थे। रवींद्र जडेजा ने चार ओवरों में 40 रन लिए थे और विकेट भी नहीं निकाल पाए थे। पीयूष चावला का अनुभव भी टीम के काम नहीं आया था। इस लेग स्पिनर ने चार ओवरों में 55 रन देकर एक विकेट लिया था। लुंगी नगिदी को आखिरी ओवर में जोफ्रा आर्चर ने चार छक्के लगाए थे, इसको अगर हटा दिया जाए तो उनका प्रदर्शन ठीक रहा था। कुरैन और दीपक चहर भी औसत प्रदर्शन कर पाए थे। पूरी संभावना है कि धोनी गेंदबाजी आक्रमण में बदले हुए नामों के साथ उतरें। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स का पहला मैच इस सीजन का अभी तक का सबसे दिलचस्प मैच था। मार्कस स्टोइनिस ने दिल्ली को बल्ले और गेंद दोनों से बचाया था। स्टोइनिस ने आखिरी तीन गेंदों पर किंग्स इलेवन पंजाब को एक रन नहीं बनाने दिया था और मैच सुपर ओवर में ले गए थे, जहां कागिसो रबादा ने दिल्ली का काम आसान कर दिया था। पंजाब के खिलाफ दिल्ली की बल्लेबाजी को पूरी तरह से फ्लॉप रही थी। पृथ्वी शॉ, शिखर धवन और शिमरेन हेटमायेर दोहरी संख्या में भी नहीं पहुंच सके थे। ऋषभ पंत और कप्तान श्रेयस अय्यर ने कुछ हद तक टीम को संभाला था, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। अंत में अगर स्टोइनिस 21 गेंदों में 53 रनों की पारी नहीं खेलते तो दिल्ली का सम्मानजनक स्कोर पाना भी मुश्किल था। टीम प्रबंधन एक मैच के बाद प्लेइंग इलेवन में बदलाव की तो शायद ही सोचे, लेकिन यह जरूर चाहेगी कि उसके बल्लेबाज काम करें। गेंदबाजी में दिल्ली को राहत है। एनरिक नोर्टजे, रबादा ने तेज गेंदबाजी आक्रमण को संभाला था। यहां मोहित शर्मा जरूर थोड़े महंगे साबित हुए थे। गेंदबाजी में टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता रविचंद्रन अश्विन की चोट है। पंजाब के खिलाफ पहले ही ओवर में दो विकेट लेकर अपनी टीम को मजबूत करने वाले अश्विन आखिरी गेंद पर रन रोकने के प्रयास में अपना कंधा चोटिल कर बैठे थे। वह मैदान के बाहर चले गए थे और फिर लौटे नहीं थे। अगर अश्विन फिट रहते हैं तो वह निश्चित तौर पर खेलेंगे, लेकिन नहीं तो उनके स्थान की भरपाई दिल्ली को करनी होगी। टीम के पास लेग स्पिनर अमित मिश्रा और संदीप लामिछाने के विकल्प हैं।

टीमें – दिल्ली कैपिटल्स – श्रेयस अय्यर (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, एलेक्स कैरी, जेसन रॉय, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिखर धवन, शिमरन हेटमायेर, अक्षर पटेल, क्रिस वोक्स, ललित यादव, मार्कस स्टोइनिस, कीमो पॉल, अमित मिश्रा, आवेश खान, हर्षल पटेल, ईशांत शर्मा, कागिसो रबाडा, मोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, संदीप लामिछाने, तुषार देशपांडे। **चेन्नई सुपर किंग्स –** महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), केदार जाधव, रवींद्र जडेजा, पीयूष चावला, ड्वायन ब्रावो, कर्ण शर्मा, शेन वाटसन, शार्दूल ठाकुर, अंबाती रायडू, मुरली विजय, फाफ डु प्लेसिस, इमरान ताहिर, दीपक चाहर, लुंगी नगिदी, मिशेल सैंटनर, केएम. आसिफ, नारायण जगदीशन, मोनू कुमार, रितुराज गायकवाड़, आर. साई किशोर, जोश हेजलवुड, सैम कुरैन।

जोंस का क्रिकेट पर बड़ा प्रभाव रहा है : आईसीसी

दुबई , एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने आस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोंस के निधन पर शोक जताया है। जोंस का गुरुवार दिल का दौरा पडने से निधन हो गया। वह आईपीएल कॉमेंट्री टीम का हिस्सा थे। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मनु स्वाहने ने एक बयान में कहा, डोन जोंस के अचानक निधन की खबर सुनकर हम काफी दुखी हैं। मैं उनके परिवार और दोस्तों को आईसीसी की तरफ से सांत्वना देना चाहता हूं। स्वाहने ने कहा, जोंस शानदार बल्लेबाज थे। वह आस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे मैच खेले और 1987 में विश्व कप जीतने वाली आस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे। एक खिलाड़ी के तौर पर, कोच के तौर पर और बाद में एक ब्रॉडकास्टर के तौर पर उनका खेल पर काफी बड़ा प्रभाव रहा है। वह क्रिकेट परिवार में सभी को याद आएंगे। जोंस ने आस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैचों में 3631 रन बनाए। आस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने 164 वनडे मैच खेले और 6,068 रन बनाए। 1986 में भारत के खिलाफ मद्रास टेस्ट में लगाया गया उनका दोहरा शतक क्रिकेट इतिहास की अतुलनीय पारियों में से एक है। यह मैच टाई रहा था। 1994 में उन्होंने संन्यास ले लिया था और गोल्फ के खेल में दिलचस्पी दिखाई थी।

गावस्कर ने विराट और अनुष्का पर आपत्तिजनक टिप्पणी की

दुबई , एजेंसी। आईपीएल मैच में कमेंट्री के दौरान सुनील गावस्कर ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के निजी जिंदगी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसका विरोध किया। कुछ लोगों ने कहा कि गावस्कर जैसे महान बल्लेबाज से इस तरह के शब्दों और भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। गावस्कर ने विराट और अनुष्का पर कमेंट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और किंग्स इलेवन पंजाब के मैच के दौरान किया। गावस्कर के बयान को यहां लिखा नहीं जा सकता। गावस्कर की टिप्पणी पर जवाब अनुष्का शर्मा की तरफ से आया। इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनुष्का ने लिखा- मिस्टर गावस्कर, आपके बयान ने मजा किरकिरा कर दिया। लेकिन, मैं अपनी तरफ से कुछ कहना पसंद करूंगी। आपको इस तरह की बात कहने की जरूरत क्या थी, जिसमें पति के खराब प्रदर्शन के लिए पत्नी को जिम्मेदार ठहराया जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि पिछले कुछ साल में आपने कमेंट्री के दौरान हर क्रिकेटर की पर्सनल और प्राईवेट लाइफ को उनको खेल से अलग रखा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि मेरे और विराट के मामले में भी यही होना चाहिए था। अनुष्का ने आगे लिखा- मुझे लगता है कि मेरे पति के खराब प्रदर्शन को बताने के लिए आपके पास कई शब्द और वाक्य जरूर रहे होंगे। क्या इसमें मेरा नाम जोड़ना ही जरूरी था? साल 2020 चल रहा है। लेकिन, मेरे लिए चीजें नहीं बदलीं। खेल के मामले में मुझे या मेरा नाम घसीटना कब बंद किया जाएगा? कब इस तरह की घटिया बयानबाजी बंद होगी।

विराट फ्लॉप रहे थे

आरसीबी के कप्तान विराट किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ सभी मोर्चों पर नाकाम रहे। फील्डिंग के दौरान उन्होंने लोकेश राहुल के दो कैच छोड़े। राहुल ने 132 रन बना दिए। बाद में आरसीबी अकेले राहुल के बराबर भी स्कोर नहीं कर सकी। विराट की बैटिंग और कप्तानी पर भी सवाल उठे। उन्होंने जोश फिलिप जैसे युवा बल्लेबाज को खुद से ऊपर से बल्लेबाजी करने भेजा। फिलिप कुछ खास नहीं कर सके। इसके बाद बैटिंग करने आए कोहली पांच गेंद पर सिर्फ एक रन बना पाए।

विराट के फैन्स नाराज

गावस्कर की टिप्पणी विराट के फैन्स को नागवार गुजरी। वे इससे नाराज हो गए। सोशल मीडिया पर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। कुछ फैन्स ने बीसीसीआई से गावस्कर को कमेंट्री पैनल से हटाने की मांग की। एक फैन ने कहा- गावस्कर जैसे लीजेंड अगर कमेंट्री के दौरान अनुष्का और विराट के निजी जीवन पर टिप्पणी करते हैं तो यह घटिया हरकत है। एक अन्य फैन ने कहा- यह बेहद शर्मनाक है। एक खिलाड़ी के जीवन में अच्छे और बुरे दौर आते रहते हैं। विराट के लिए गुरुवार का मैच अच्छा साबित नहीं हुआ।

आप सम्मान खो चुके हैं

विराट के फैन्स ही क्यों कुछ सामान्य क्रिकेट प्रशंसकों ने भी गावस्कर के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। एक यूजर ने कहा- गावस्कर साहब आप हमारी नजरों में गिर चुके हैं, सम्मान खो चुके हैं। यह बयान बयान आपकी मानसिकता का परिचय देने के लिए काफी है। एक अन्य यूजर ने कहा- गावस्कर को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए।

हेवर्ट्ज की हैट्रिक से चेल्सी को मिली आसान जीत, बर्न्सले को 6-0 से हराया

नई दिल्ली , एजेंसी।

इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने काराबाओ कप में बर्न्सले पर 6-0 से बड़ी जीत दर्ज की है। टीम के लिए तीसरा ही मैच खेल रहे केई हेवर्ट्ज ने हैट्रिक लगाई। उन्होंने 28वें, 55वें और 65वें मिनट में गोल किया। हेवर्ट्ज 2020 में अभी तक 26 गोल में शामिल रहे हैं। जिसमें 18 गोल और 8 असिस्ट हैं। यूरोप के टॉप-5 लीग में रॉबर्ट लेवानडोस्की (35), लियोनल मेसी (32) और रोनाल्डो (31) ही उनसे आगे हैं। उनके अलावा टैमी अब्राहम ने 19वें, रॉस बार्कले ने 49वें जबकि ओलिवियर गिराउड ने 83वें मिनट में गोल किया। जीत के साथ टीम चौथे राउंड में पहुंच गई है। वहीं एक अन्य मुकाबले में आर्सनल ने लिस्टर सिटी को 2-0 से हराया। इसके अलावा फुल्हम, ब्राइटन और एवर्टन ने भी अपने-अपने मुकाबले जीते।

सुआरेज एटलेटिको मैड्रिड से जुड़े

स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के स्ट्राइकर लुईस सुआरेज स्पेन में ही रहेंगे। वे एटलेटिको मैड्रिड से जुड़ गए हैं। 2014 में बार्सिलोना से जुड़े सुआरेज ने क्लब के लिए 283 मैचों में 198 गोल किए हैं। वहीं फ्रेंच क्लब पीएसजी के मिडफील्डर एंजेल डि मारिया पर 4 मैच का बैन लगा है। इसी महीने पीएसजी और मार्सेले के मैच के दौरान हुए विवाद की वजह से उन पर बैन लगा है

18 साल के यशस्वी ने धोनी को नमस्ते किया

दुबई | एजेंसी।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद महेंद्र सिंह धोनी का क्रेज कम नहीं हुआ। फैन्स हों या प्लेयर। धोनी का हर कोई मुरीद है। क्रिकेट सर्कल्स में उनको सम्मान से देखा जाता है। धोनी से जुड़ी तीन खबरों का जिक्र करते हैं। इनमें से दो आईपीएल की हैं। शारजाह में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच से पहले टॉस के वक्त स्टीव स्मिथ समेत कई खिलाड़ियों ने धोनी से हाथ मिलाया। इस दौरान पहली बार इस लीग में खेलने आए 18 साल के यशस्वी जयसवाल भी मौजूद थे। वे जैसे ही धोनी के करीब पहुंचे तो दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। माही ने भी उनसे कुछ देर बातचीत की। यशस्वी के सीनियर के प्रति इस सम्मान की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। फैन्स ने यशस्वी के इस व्यवहार की खुले दिल से तारीफ की। यशस्वी मुंबई की टीम से रणजी खेलते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। यशस्वी को राजस्थान रॉयल्स ने 2.4 करोड़ में खरीदा था अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल चुके यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स ने 2.4 करोड़ में खरीदा था। जायसवाल लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। यशस्वी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल में अपना पहला मैच खेला। हालांकि इस मैच में वह केवल 6 रन ही बना पाए।

धोनी की तरह हेलिकॉप्टर शॉट लगाना चाहते हैं स्मिथ

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ हेलिकॉप्टर शॉट लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह धोनी का पसंदीदा शॉट है। जिसमें वे यॉर्कर को भी बाउंड्री के बाहर भेज सकते हैं। कुछ वक्त से हार्दिक पांड्या भी यह शॉट खेल रहे हैं।

2007 में आज ही के दिन टीम इंडिया ने टी-20 वर्ल्ड कप जीता था।

धोनी एंड टीम सीजन का तीसरा मैच खेलने उतरेगी

दुबई | एजेंसी।

आईपीएल के 13वें सीजन का 7वां मैच चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के बीच आज दुबई में खेला जाएगा। चेन्नई का इस सीजन में तीसरा मैच है, जबकि दिल्ली के लिए यह दूसरा मैच होगा। दिल्ली के खिलाफ चेन्नई का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। पिछले 5 मुकाबलों में चेन्नई ने 4 मैच जीते हैं। पिछले सीजन में दोनों के बीच खेले गए 3 मुकाबलों में चेन्नई ने दिल्ली को शिकस्त दी थी। दोनों टीमों के बीच दुबई में यह पहला मैच होगा।

धोनी के बैटिंग ऑर्डर पर उठे थे सवाल

राजस्थान के खिलाफ पिछले मैच में धोनी के 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। धोनी से पहले सैम करेन, रविंद्र जडेजा और केदार जाधव को बल्लेबाजी करने भेजा गया था। मैच में चेन्नई को 16 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद बैटिंग ऑर्डर को लेकर धोनी को आलोचना झेलनी पड़ी थी।

रायडू और ब्रावो के खेलने पर संशय

चेन्नई के लिए अंबाती रायडू और ड्वेन ब्रावो के खेलने को लेकर संशय बना हुआ है। रायडू हैम स्ट्रिंग की परेशानी की वजह से राजस्थान के खिलाफ पिछला मुकाबला नहीं खेले थे। वहीं ब्रावो इस सीजन के शुरुआती दोनों मैच से बाहर रहे थे। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों के इस मैच में खेलने पर संशय बना हुआ है।

इन रिकॉर्ड्स पर रहेगी नजर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर आने के लिए एमएस धोनी को 2 छक्कों की जरूरत है। 100 छक्के का आंकड़ा छूने के लिए शिखर धवन को 4, जबकि ऋषभ पंत को 6 छक्के की जरूरत है। आज जीती तो 3 टीमों के खिलाफ 15+ मैच जीतने वाली दूसरी टीम होगी सीएसके तीन बार की चैम्पियन (2018, 2011, 2010) सीएसके यदि यह मैच जीत लेती है, तो 3 टीमों के खिलाफ 15 से ज्यादा मैच जीतने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। इसके पहले मुंबई इंडियंस ही ऐसा कर सकी है।

दोनों टीम के महंगे खिलाड़ी सीएसके में कप्तान धोनी सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। टीम उन्हें एक सीजन के 15 करोड़ रुपए देगी। उनके बाद टीम में केदार जाधव का नाम है, जिन्हें इस सीजन में 7.80 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं, दिल्ली में ऋषभ पंत 15 करोड़ और शिमरॉन हेटमायर 7.75 करोड़ रुपए कीमत के साथ सबसे महंगे प्लेयर हैं। आईपीएल में चेन्नई और दिल्ली के बीच धोनी की टीम का ही पलड़ा भारी रहा है। दोनों के बीच अब तक 21 मुकाबले खेले गए। चेन्नई ने 15 और दिल्ली ने 6 मैच जीते हैं। पिछले सीजन में दिल्ली एक बार भी चेन्नई को नहीं हरा पाई थी।

यूएई में दिल्ली का खराब रिकॉर्ड, चेन्नई ने 5 में से 4 मैच जीते

लोकसभा चुनाव के कारण आईपीएल 2009 में साउथ अफ्रीका और 2014 सीजन के शुरुआती 20 मैच यूएई में हुए थे। तब यूएई में दिल्ली का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा था। टीम ने तब यहां 5 में से 2 मैच जीते और 3 हारे थे। वहीं चेन्नई ने यूएई में 5 में से 4 मैच जीते थे। दिल्ली ने सुपर ओवर में पंजाब को हराया था इस सीजन में दिल्ली ने अपना पिछला मुकाबला पंजाब के खिलाफ दुबई में ही खेला था। जिसका फैसला सुपर ओवर में निकला था। सुपर ओवर में दिल्ली ने पंजाब को सिर्फ 3 रन पर ही रोक दिया था।

पिच और मौसम रिपोर्ट

दुबई में मैच के दौरान आसमान साफ रहेगा। तापमान 27 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिच से बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है। यहां स्लो विकेट होने के कारण स्पिनर्स को भी काफी मदद मिलेगी। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। इस आईपीएल से पहले यहां हुए पिछले 61 टी-20 में पहले बल्लेबाजी वाली टीम की जीत का सक्सेस रेट 55.74त रहा है।

इस मैदान पर हुए कुल टी-20- 61

पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती- 34
पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती- 26
पहली पारी में टीम का औसत स्कोर- 144
दूसरी पारी में टीम का औसत स्कोर- 122

विक्रांत-यामी की फिल्म गिन्नी वेड्स सनी का पहला गाना लोल रिलीज़

बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी और यामी गौतम की आने वाली फिल्म गिन्नी वेड्स सनी का पहला गाना लोल रिलीज़ हो गया है। गिन्नी वेड्स सनी का पहला गाना लोल' रिलीज़ कर दिया गया है। यह गाना सोनी म्यूजिक इंडिया के बैनर तले रिलीज़ किया गया है। गाने में विक्रांत और यामी की जोड़ी को खूब पसंद किया जा रहा है। इस गाने को पायल देव ने कंपोज कर देव नेगी के साथ मिलकर स्वरबद्ध भी किया है। इस गाने को कुणाल वर्मा ने लिखा है। सोनी म्यूजिक इंडिया के सीनियर डायरेक्टर - मार्केटिंग, सानुजीत भुजबल का मानना हैं कि गिन्नी वेड्स सनी' एक फील गुड फिल्म है, और म्यूज़िक फिल्म की कहानी का एक अभिन्न हिस्सा है। हम इस फिल्म का पहला गाना लोल रिलीज कर दर्शकों और श्रोताओं का मूड सेट करना चाहते हैं जिससे वे इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम से उम्मीद बनाए रखें। मैं पायल देव, कुणाल और देव की सराहना करता हूं कि उन्होंने मिलकर इतना बेहतरीन गाना बनाया है। पायल देव का मानना है कि मुझे इस गाने को कंपोज करने में बहुत मज़ा आया।कुणाल ने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है, युवा पीढ़ी इस गाने से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। इस तरह की क्रिएटिव कंपोजिशन पर नियंत्रण रखने की सबसे खास बात यह है कि आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं। मुझे इस गाने को बनाने के लिए पूरी छूट दी गई थी ताकि मैं एक अच्छा और मज़ेदार गाना बना सकूं। मुझे लोगों कि प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार है।

दीपिका, सोनम के साथ काम करना पसंद करेंगी मिंडी कलिंग

भारतीय मूल की अमेरिकी अभिनेत्री मिंडी कलिंग ने भारतीय सिने स्टार्स में दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर को चुना है, जिनके साथ वह काम करना पसंद करेंगी। मिंडी से उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में पूछे जाने पर और यह सवाल करने पर कि वह बॉलीवुड फिल्म में किसके साथ काम करने की इच्छुक हैं, इस पर उन्होंने बताया, मुझे सोनम कपूर या दीपिका पादुकोण के साथ काम करना अच्छा लगेगा। वे दोनों बहुत प्रतिभाशाली हैं। फिलहाल मिंडी प्रियंका चोपड़ा के साथ काम कर रही हैं। दोनों अभिनेत्रियां आगामी शादी पर आधारित कॉमेडी में साथ काम कर रही हैं। कलिंग ने कहा, प्रियंका बहुत ही स्मार्ट हैं। उनके साथ काम करना शानदार है। अपने प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने कहा, मैंने अभी स्क्रिप्ट पूरी की है। फिल्म को न्यूयॉर्क और भारत में फिल्माया जाना है। उनकी और मेरी जोड़ी बहुत ही मजेदार, डायनामिक है, मैं उसे बनाने का इंतजार नहीं कर पा रही हूं। यह फिल्म एक बड़ी खचीलीं भारतीय शादी पर आधारित है, जिसमें संस्कृति का टकराव दिखाए जाने की संभावना है। मिंडी का आखिरी प्रोजेक्ट नेवर हैव आई एवर थी, जो काफी हिट हुई थी।

धांसू है जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2 का पोस्टर, ईद पर होगी रिलीज

बॉलिवुड ऐक्टर जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते को काफी पसंद किया गया था। अब इस फिल्म का सीच्ल सत्यमेव जयते 2 बन रहा है जिसका फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इस फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें जॉन अब्राहम का लुक गजब का लग रहा है। इस पोस्टर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी गई है।

फिल्म में इस बार जॉन अब्राहम के साथ लीड रोल में दिव्या खोसला कुमार दिखाई देंगी। यह फिल्म अगले साल ईद पर यानी 12 मई 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इस पोर्टर को शेयर करते हुए जॉन अब्राहम ने लिखा, जिस देश की मैया गंगा है, वहां खून भी तिरंगा है। दिव्या खोसला कुमार लंबे समय बाद इस फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर मिलाप जावेरी लॉकडाउन के दौरान फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। माना जा रहा है कि अगले महीने अक्टूबर 2020 में इसकी शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। फिल्म की शूटिंग लखनऊ में की जाएगी। इस बारे में मिलाप जावेरी ने कहा, हमने फिल्म के शूट की लोकेशन मुंबई से बदलकर लखनऊ की है ताकि कहानी को और दमदार बनाया जा सके।

सेक्रेड गेम्स 2 में इंटिमेट सीन की शूटिंग में अनुराग ने की थी मदद-एलनाज नौरोजी

अनुराग कश्यप इन दिनों सेक्शुअल हैरासमेंट का आरोप झेल रहे हैं। ऐक्ट्रेस पायल घोष ने उन पर ये आरोप लगाया है। अनुराग पर ये इल्जाम लगने के बाद उनके साथ काम कर चुकी कई ऐक्ट्रेसस उनके सपोर्ट में आ चुकी हैं। अब सेक्रेड गेम्स में जोया/जमीला का रोल प्ले करने वाली एलनाज नौरोजी ने भी उनके पक्ष में आई हैं और पुराना किस्सा शेयर किया है। एलनाज ने बताया कि एक सेक्स सीन के लिए वह असहज थीं तो कैसे अनुराग ने उनकी मदद की थी। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, मुजे याद है कि एक खास सेक्स सीन की वजह से मैं सेक्रेड गेम्स 2 छोडने वाली थी। प्रोडक्शन हाउस और मेरी टीम के बीच काफी बातचीत के बाद, अनुराग सर ने मुझे मेसेज किया और कहा, सुनो, परेशान मत हो, मैं रास्ता निकालूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। मेरा सीजन 1 में उनके साथ बस 1 शॉट था और मैं उन्हें इतना जानती भी नहीं थी कि भरोसा कर सकूं लेकिन राजी हो गई। जिस दिन वो सीन शूट होना था, मुझे पूरे क्त घबराहट रही, मुझे लगा कि अब तो मैं सेट्स पर हूं और ये लोग कैसे भी करके मुझसे वो सीन करवा लेंगे। मैं न नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मुझसे कहा गया था कि स्क्रिप्ट में बदलाव नहीं होगा। मुझे सेट पर बुलाया गया और अनुराग सर ने मुझे समझाना शुरू किया कि वह इसे कैसे शूट करेंगे कि इस बात का खयाल रहे कि मैं क्या करने में असहज हूं। मुझे रोना आ गया, मुझे रोना आ गया क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरी बात का ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे शूट करेंगे कि मुझे दिक्कत न हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीन मेरे कपड़े बिना उतारे शूट किया जाएगा जबकि वह अलग तरह से लिखा गया था। मुझे रोना आया क्योंकि उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया और अपनी बात रखी। जब सीन शूट हो गया तो मैं अपनी वैनिटी में जाकर रोई और उन्हें लंबा मेसेज लिखा और उन्हें ऐसा आदमी होने के लिए धन्यवाद दिया। हमें बॉलिवुड में उनके जैसे और मर्दों/इंसानों/डायरेक्टर्स की जरूरत है। सिर्फ बॉलिवुड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। शुक्रिया मेरे अंदर भरोसा कायम रखने और मुझे अपने सेट पर सेफ महसूस करवाने के लिए। बीते रविवार पायल ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पायल को घर बुलाकर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। पायल के इस आरोप के बाद अनुराग की दोनों एक्स-वाइफ आरती बजाज और कल्कि केकलां उनके सपोर्ट में आ गई थीं।

एक्ट्रेस टिया बाजपेयी ने करवाया अपना ड्रग टेस्ट

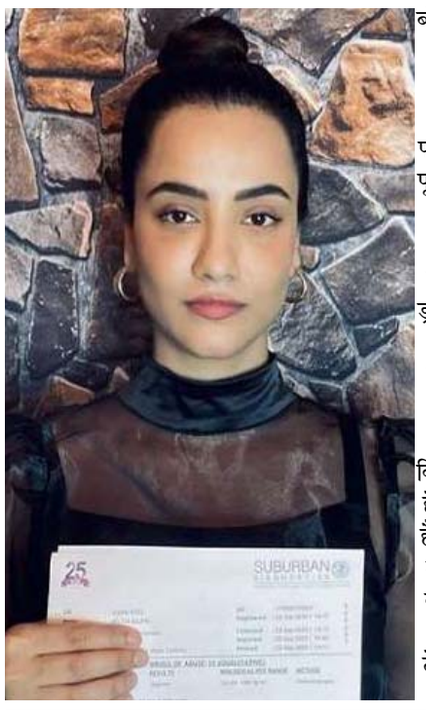

बॉलीवुड में इन दिनों ड्रग्स का मुद्दा गर्माया हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ से इस सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को रकुलप्रीत एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुईं। वहीं, दीपिका पादुकोण, सारा अली ख़ान और श्रद्धा कपूर से 26 सितम्बर को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। दीपिका और सारा गोवा में थीं। दोनों बुधवार को ही मुंबई पहुंच गयीं। इस बीच एक्ट्रेस टिया बाजपेयी ने एक अनोखा क़दम उठाया है। टिया ने बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री को बदनामी से बचाने के लिए अपना ड्रग टेस्ट करवाया और इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके दूसरे लोगों से भी स्वैच्छिक तौर पर टेस्ट करवाने की गुज़ारिश की ताकि पूरी इंडस्ट्री पर सवालिया निशान ना लगें। टिया ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो कहती हैं- इस वक़्त मनोरंजन उद्योग को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं। इसलिए मैंने अपना ड्रग टेस्ट करवाया है, जो नेगेटिव आया है। मैं आप सब लोगों से गुज़ारिश करूंगी कि सभी को एक रंग में ना रंगें। हम में से कुछ वाकई गंभीरता के साथ अपना काम करते हैं और वाकई बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मैं अपने सभी साथी कलाकारों से गुज़ारिश करती हूं कि वे अपना ड्रग टेस्ट करवाएं और इसे सार्वजनिक कर दें। अपने परिवार, काम और फैंस के लिए इसे ट्वीट करें।

बेल बॉटम के लिए अक्षय कुमार ने तोड़ दिया अपना 18 साल पुराना नियम

अक्षय कुमार इस समय अपनी आने वाली फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग में लगे हुए हैं। फिल्म की शूटिंग इस समय स्कॉटलैंड में चल रही है। इस फिल्म की शूटिंग कोरोना वायरस के कारण काफी टाइम तक रुकी रही। इसलिए अक्षय कुमार ने बेल बॉटम के लिए अपना एक 18 साल पुराना नियम तोड़ दिया है जिसे जानकर सभी लोग हैरान हैं। हालांकि अक्षय के इस काम से प्रड्यूसर को काफी फायदा हो रहा है। दरअसल पिछले 18 सालों से अक्षय कुमार ने नियम बना रखा है कि वह दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। लेकिन बेल बॉटम के लेट होने के कारण उन्होंने अपना यह नियम तोड़ दिया है और खुद ही डबल शिफ्ट में काम करने की सलाह दी है। अक्षय के इस फैसले के बाद फिल्म की शूटिंग दोगुनी रफ्तार से हो रही है और प्रड्यूसर का काफी पैसा बच रहा है। फिल्म की शूटिंग 2 यूनिट कर रही हैं। पहली यूनिट के शूट पूरा करने के बाद एक लोकल टीम दूसरी शिफ्ट की शूटिंग संभालती है। फिल्म के प्रड्यूसर जैकी भगनानी ने कहा, अक्षय सर पूरी तरह से प्रड्यूसर के ऐक्टर है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूं। वह हमेशा सभी के बारे में सोचते हैं, वह पूरी तरह सोने के बने हुए हैं। अक्षय सर पिछले 18 साल में पहली बार डबल शिफ्ट कर रहे हैं ताकि फिल्म को समय से पूरा किया जा सके। बता दें कि बेल बॉटम में अक्षय कुमार भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। अक्षय के अलावा फिल्म में वाणी कपूर, लारा दत्ता और हुमा कुरैशी लीड रोल में हैं। हाल में फिल्म के कुछ पोस्टर और तस्वीरें रिलीज की गई थीं जिसके बाद फैन्स इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

बिग बॉस 14 शो में शामिल होने की खबरों को टीना दत्ता ने झुठलाया

टेलीविजन अभिनेत्री टीना दत्ता ने रिएलिटी शो बिग बॉस 14 में शामिल होने की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। धारावाहिक उतरन से चर्चा में आईं टीना ने इंस्टाग्राम पर एक नोट लिखकर मामले पर अपनी सफाई दी है। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, मेरे फेवरेट बिग बॉस के नाम मेरा लव लेटर।

टीना लिखती हैं, प्यारे बिग बॉस, क्या आपको पता है कि आपसे कितना प्यार किया जाता है? बताती हूं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हे भगवान! जब से आपके साथ मेरे काल्पनिक रिश्ते की शुरूआत हुई है, तब से मेरा फोन नॉन स्टॉप बजता ही रहता है। मैं उस लड़की की तरह महसूस कर रही हूं, जो अभी-अभी रिश्ते में आई है। मीडिया से कॉल आ रहे हैं, हम दोनों को लेकर हेडलाइन्स सामने आ रही हैं, काफी उत्सुकता है। मैं सोच रही हूं कि ये खिचड़ी पकी है कैसे? मेरे प्रिय, हमारी जोड़ी न तो स्वर्ग में बनी है और न ही धरती पर और न ही भारतीय टेलीविजन में, लेकिन याद रखना मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूं, लेकिन एक दर्शक के तौर पर, प्रतिभागी के तौर पर नहीं। लव टीनजी टीना दत्ता। सलमान खान द्वारा संचालित बिग बॉस 14 को 3 अक्टूबर से कलर्स टीवी पर प्रसारित किया जाएगा।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के लिए छलका इंडस्ट्री का दर्द

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बुरी खबरों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं रहा। बॉलिवुड के दिग्गज सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है। आज शुक्रवार दोपहर उन्होंने 1 बजकर 4 मिनट पर अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर ने एक बार फिर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। लगातार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग उनके लिए सोशल मीडिया पर शोक जता रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लता मंगेशकर ने भी एसपी बाला सुब्रमण्यम के लिए ट्वीट कर दुख जताया है। वह बीते महीने कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिसके बाद पिछले दिनों उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई।लता मंगेशकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रतिभाशाली गायक, मधुरभाषी, बहुत नेक इंसान एसपी बाला सुब्रमण्यम जी के स्वर्गवास की खबर सुनकर मैं बहुत व्यथित हूं। हमने कई गाने साथ गाए, कई शोज़ किए। सब बातें याद आ रही हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। रितेश देशमुखे ने लिखा, हम बने तुम बने एक-दूजे के लिए। एसपी बाला सुब्रमण्यम जी, थैंक यू शानदार म्यूजिक के लिए। भरे दिल से मैं कह रहा हूं- साथिया या तूने क्या किया? परिवार, चाहने वालों और दुनिया भर के लाखों के लिए संवेदनाएं। ऐक्टर राम चरण ने लिखा, मैं यह जानकर हैरान हूं कि हमारे हंसमुख एसपी बाला सुब्रमण्यम अब नहीं रहे। इंडस्ट्री में यह लॉस अकल्पनीय है। मेरी संवेदना पूरी फैमिली के साथ है। बता दें कि एसपी बाला सुब्रह्मण्यम ने 16 भारतीय भाषाओं में लगभग 40 हजार से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्हें पद्मश्री (2001) और पद्मभूषण (2011) जैसे सम्मानों सहित कई अवॉर्ड्स भी मिले हैं।

इतना ही नहीं एसपी बाला सुब्रमण्यम ने पहली हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए (1981) में काम किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें नैशनल फिल्म अवॉर्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर मिला था। 1989 में उन्होंने सलमान खान के लिए गाना शुरू किया और उनकी आवाज बन गए। उन्होंने मैंने प्यार किया में सलमान के गानों को आवाज दी थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और गाने आज भी पसंद किए जाते हैं।

भाभी जी घर पर है में सौम्या टंडन को रिप्लेस करेंगी नेहा पेंडसे?

टीवी के कंट्रोवर्सियल शो बिग बॉस के बारहवें सीजन में नजर आ चुकी एक्ट्रेस नेहा पेंडसे के फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। खबरें है कि नेहा पेंडसे को एंड टीवी के कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है के लिए अप्रोच किया गया है। सुनने में आ रहा है कि नेहा पेंडसे इस शो में सौम्या टंडन को रिप्लेस करने वाली है। बीते 5 साल से सौम्या टंडन इस शो से जुड़ी रही और अनीता भाभी के किरदार में उन्होंने जान फूंक दी थी। निजी वजहों के चलते हाल ही में सौम्या टंडन ने इस शो को अलविदा कह दिया था। सौम्या टंडन के इस फैसले ने मेकर्स की रातों की नींद तो उड़ा दी थी लेकिन अब लगता है कि उन्हें उनकी नई अनीता भाभी मिल ही गई है। भाभी जी घर पर है से जुड़े सूत्रों ने स्पॉटबॉयई को जानकारी दी है कि, शो की प्रोड्यूसर बेनिफर कोहली अनीता भाभी के रूप में नेहा पेंडसे को लेने के लिए काफी उत्सुक है। उनके पुराने शो में नेहा ने लीड रोल अदा किया था और उन्हें अब इस रोल के लिए भी वो ही जंच रही है। अभी तक नेहा ने इस ऑफर का जवाब नहीं दिया है।

रणबीर-श्रद्धा की जोड़ी मचायेगी धूम

बॉलीवुड के रॉकस्टार रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाती नजर आ सकती है। प्यार का पंचनामा', सोनू के टीटू की स्वीटी ' जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके निर्देशक लव रंजन अपनी अगली फिल्म में एक नई जोड़ी पेश करेंगे। लव रंजन की फिल्म में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं। लव रंजन की यह फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें श्रद्धा कूपर एक वेट्रेस की भूमिका में नजर आएंगी, वहीं रणबीर कूपर लवर ब्वॉय के रोल में होंगे। बताया जा रहा है कि वर्ष के शुरुआती महीनों में ही फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी लेकिन कोरोना महामारी के चलते ऐसा नहीं हो सका। हालांकि, अब कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि नवंबर में रणबीर और श्रद्धा मुंबई में इस फिल्म पर काम शुरू करने वाले हैं। मुंबई शेड्यूल के बाद, टीम एक मैराथन शूट के लिए स्पेन जाएगी।फिल्म की शूटिंग लगभग छह महीने चलेगी और अगले साल अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी।

कंचन उजाला
हिंदी दैनिक
स्वामी नमोकंचन कार्पोरेट सर्विसेस (एल.एल.पी) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक कंचन सोलंकी द्वारा उमाकान्ती ऑफसेट प्रेस, ग्राम डेहवा पोस्ट मोहनलाल गंज लखनऊ से मुद्रित एवं 61/18 चुटकी भण्डार हुसैनगंज लखनऊ से प्रकाशित।
संपादक- कंचन सोलंकी
TITLE CODE- UPHIN48974
Mob: 8896925119, 9695670357
Email: kanchansolanki397@gmail.com
नोटः समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारो एवं लेखों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नही। समस्त विवादो का निस्तारण लखनऊ न्यायालय के अधीन होगा।